बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 68

मुद्रास्फीति की चुनौती

मुद्रास्फीति की गति का आकलन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो चुका है। उदाहरण के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व तथा विकसित और विकासशील देशों के कई अन्य केंद्रीय बैंकों का मानना था कि महामारी के बाद उपभोक्ता कीमतों में इजाफा अस्थायी प्रकृति का था। बहरहाल, निरंतर ऊंची मुद्रास्फीति दर ने आखिरकार उन्हें समायोजन के लिए विवश किया। इसकी वजह से 2022 में पूरी दुनिया में नीतिगत दरों में तेज और समन्वित इजाफा हुआ और वैश्विक वित्तीय हालात में तंगी की स्थिति बन गई। उच्च ब्याज दर ने असर डाला और दुनिया भर में मुद्रास्फीति में कमी आई। इससे वित्तीय बाजारों में यह आशावाद फैला कि फेडरल रिजर्व जल्दी ही नीतिगत दरों में कमी शुरू करेगा। फेड के अपने अनुमानों में भी संकेत दिया गया कि वह 2024 में फेडरल फंड दरों में 75 आधार अंकों की कमी करेगा। ये संकेत फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के बाद दिया गया था। बहरहाल, फरवरी की तुलना में मार्च में मुद्रास्फीति के बढ़कर 3.5 फीसदी हो जाने के बाद एक बार फिर यह सवाल पैदा हो गया कि यह कितनी जल्दी फेडरल रिजर्व के मध्यम अवधि के दो फीसदी के लक्ष्य तक पहुंच सकेगी। फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने गत सप्ताह एफओएमसी की बैठक के बाद अनुमान जताया था कि नीतिगत ब्याज दर लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है। पॉवेल ने यह भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि फेड का अगला कदम ब्याज दरों में इजाफे के रूप में सामने आए। अधिकांश बाजार प्रतिभागियों को उम्मीद नहीं है कि फेडरल रिजर्व नीतिगत दरों में इजाफा करेगा। परंतु अंतिम सिरे तक अपस्फीति मुश्किल हो सकती है और इसके लिए बाजार की अपेक्षाओं में समायोजन की जरूरत पड़ सकती है। 10 वर्ष के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल में मार्च के अंत से करीब 30 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है। अब लंबे समय के लिए नए सिरे से उच्च आकांक्षा अमेरिका तथा शेष विश्व को प्रभावित करेगी।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में कहीं अधिक मजबूती दिखाई है जो अधिकांश विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर है। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में चालू वर्ष के लिए वृद्धि अनुमानों को 60 आधार अंकों से संशोधित किया। परंतु लंबे समय तक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति को जारी रखने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसका असर वैश्विक वृद्धि पर भी पड़ेगा। अमेरिका में अगर लंबे समय तक उच्च ब्याज दर कायम रही तो इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता आएगी। उदाहरण के लिए जापान के केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह कम से कम दो बार हस्तक्षेप किया ताकि येन की मदद कर सके जो 34 वर्षों के निचले स्तर तक गिर गया था। कई मुद्राओं खासकर विकासशील देशों की मुद्राओं पर और अधिक दबाव बनने की आशंका है।

भारत के लिए इसमें क्या संदेश है? अमेरिकी तथा वैश्विक वृद्धि पर दबाव व्यापारिक चैनलों के जरिये भारत में उत्पादन पर असर डालेगा। बहरहाल मुद्रा के मोर्चे पर भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। हाल के दिनों में रुपये की स्थिरता से इसे महसूस किया जा सकता है। बीते एक वर्ष में डॉलर की तुलना में रुपये में केवल दो फीसदी गिरावट आई है। लंबी अवधि तक ऊंचा रहने से पूंजी के बाहर जाने का जोखिम होता है लेकिन संभव है इससे बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर न जाए क्योंकि भारत का वृद्धि परिदृश्य और ब्याज दरें अपेक्षाकृत बेहतर हैं। अनुमानों में संभावित बदलाव शायद मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णयों पर असर न डाले। मौद्रिक नीति समिति का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर औसतन 4.5 फीसदी रहेगी जो चार फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है। अनुमान से बेहतर वृद्धि नतीजों को देखते हुए नीतिगत दरों में जल्दी कटौती का भी कोई दबाव नहीं है।

बिनय सिन्हा

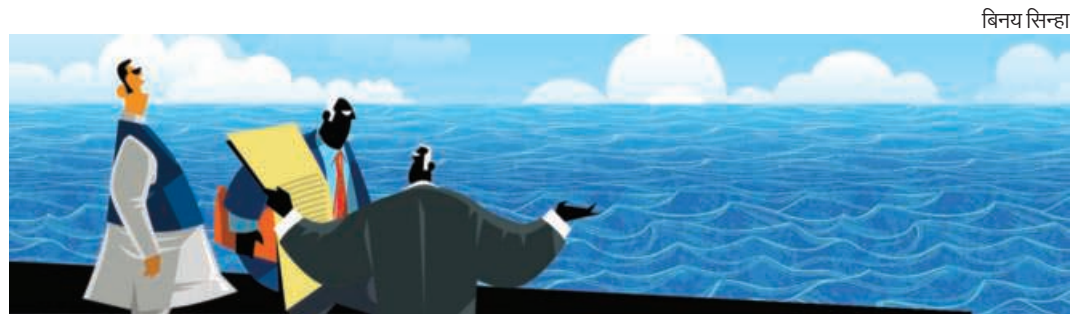

समुद्र के लिए गति शक्ति जैसे कार्यक्रम की जरूरत

भारत की जलीय अर्थव्यवस्था रणनीति इस बात पर निर्भर है कि हम जमीन के नीचे मजबूत विकास को लेकर जागरूक हों। यह एक अहम क्षेत्र है जिसकी अनदेखी की गई है। बता रहे हैं अजय कुमार

महासागरों में बहुत व्यापक आर्थिक संभावनाएं हैं जिनका लाभ अभी नहीं उठाया जा सका है। आर्थिक पैमाने पर ये लाखों करोड़ डॉलर तक हो सकती हैं लेकिन इसके बावजूद इनके बहुत सारे हिस्सों के बारे में हम नहीं जानते। न केवल 94 प्रतिशत जीवन समुद्र के भीतर है, बल्कि समुद्र ग्रीनहाउस गैसों के प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड-ओशन रिज जो करीब 65,000 किलोमीटर लंबी है, वह भी समुद्र के भीतर है। समुद्र के भीतर 30 लाख जहाजों का मलबा पड़ा है जिनमें से प्रत्येक के साथ कहानियों का पूरा जखीरा है। आश्चर्य की बात है कि समुद्र की उतनी भी पड़ताल नहीं हुई है जितनी चांद या मंगल की सतह की।

भारत का समुद्री क्षेत्र उसके भूभाग के ही बराबर है और हमारे 80 फीसदी संसाधन समुद्र में हैं लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उसका योगदान केवल चार फीसदी है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में जलीय या समुद्री अर्थव्यवस्था में बहुत अवसर छिपे हुए हैं। भारत मछलीपालन, जलीय पर्यटन, नौवहन, तटीय ऊर्जा और खनिज आदि की मदद से लाखों रोजगार और लाखों करोड़ रुपयों का राजस्व जुटा सकता है। समुद्र में मछली मारने के हिसाब से चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है और भारत को उसकी बराबरी करनी है। गहरे समुद्र के खनिजों की बात करें तो पॉलिमेटालिक नॉड्यूल्स और दुर्लभ खनिजों सहित वहां असीमित संभावनाएं हैं। बेहतर तकनीक के साथ निकट भविष्य में उनका निरंतर खनन भी आसान होता जाएगा। जो देश समुद्री क्षेत्रों में जल्दी पकड़ बनाएगा वही लंबी अवधि में संसाधनों और क्षेत्र पर काबिज होगा। समुद्री अर्थव्यवस्था की रणनीति बेहतर जलीय क्षेत्र जागरूकता यानी अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (यूडीए) पैदा करने पर निर्भर है जिसकी मोटे तौर पर अनदेखी की गई है। इस क्षेत्र को शीत युद्ध के दौरान पहली बार तवज्जो मिली और अमेरिकी नौसेना ने अटलांटिक सागर में एसओएसयूएस जैसे समुद्री सतह वाले हाइड्रोफोन नेटवर्क की स्थापना की ताकि रूसी समुद्री पनडुब्बियों की निगरानी की जा सके। बहरहाल, तकनीकी उन्नति के साथ यूडीए का आर्थिक महत्त्व भी बढ़ा है। अब पानी के भीतर की जानकारी पानी के भीतर तथा अंतरिक्ष में मौजूद सेंसरों की मदद से निकाली जाती है। अंतरिक्ष स्थित सेंसरों की मदद से मछली मारने वाली नौकाओं को महंगी मछलियों को पहचानने और ज्यादा मछलियों वाले इलाकों में जाने में मदद की जाती है।

भारत को पानी के भीतर काम करने वाली स्वदेशी सेंसर तकनीक विकसित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ये तकनीक बहुत अधिक महंगी हैं और इसलिए उनका आर्थिक उपयोग अव्यावहारिक हो जाता है। इसके अलावा शीत युद्ध के दौर में उपकरण प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कम तापमान वाले इलाकों में कारगर रहता है लेकिन हिंद महासागर जैसे अपेक्षाकृत गर्म इलाके में उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ जाता है। यहां उसके आंकड़े 60 फीसदी तक गलत साबित होते हैं। भारत में अगस्त 2022 में नौसेना के स्प्रिंट कार्यक्रम के तहत 75 आईडेक्स के साथ अच्छी शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरूप देश में पहली बार स्वदेशी तकनीक के नमूने बनाए गए जो पानी के भीतर काम करते हैं। जल के भीतर काम करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने के लिए घरेलू चिप विकास क्षमता जरूरी है। एक डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिये ऐसी प्रणालियों के लिए सेंसर विकास को फंड किया जा सकता है और चिप तैयार करने को भी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सरकार की ओर से खरीद की गारंटी के साथ आईडेक्स जैसी प्रणालियों पर विचार कर सकता है।

ऐसी प्रणालियों में बहुत अधिक आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इनमें ढेर सारी सूचनाएं होती हैं, मिसाल के तौर पर समुद्र में स्थित भौगोलिक आकृतियां, वहां घटित होने वाली घटनाएं आदि। इसके अलावा नेविगेशन, संचार, तापमान, क्षारीयता जैसे पर्यावरण कारक, पानी की गुणवत्ता और रासायनिक घटक, समुद्री धाराएं, संकेत और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आदि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालय, संगठन, तटीय राज्य अलग-अलग आंकड़े एकत्रित करते हैं जिससे अलहदा आंकड़े तैयार होते हैं।

यूपीआई और आधार के तर्ज पर एक ओपन एपीआई आधारित ढांचा आंकड़ों की साझेदारी का माध्यम बन सकता है। इसमें स्टार्टअप और विभिन्न संगठनों द्वारा ऐप्लिकेशन विकास मददगार हो सकता है और इस क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जिस तरह स्थलीय आर्थिक विकास के लिए पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है, वैसे ही समुद्र के भीतर की आर्थिक संभावनाओं के लिए भी पीएम गति शक्ति की शुरुआत की जा सकती है। यह पहल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक व्यापक तस्वीर पेश करेगी और मजबूती और खामियों का पता लगा सकेगी और विभिन्न एजेंसियों के लिए केंद्रीकृत समन्वय प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी।

आर्थिक यूडीए के लिए पीएम गति शक्ति को जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म से विशिष्टीकृत किया जा सकता है। चूंकि तापमान, खारापन, घनत्व आदि हमेशा बदलते रहते हैं इसलिए इस प्लेटफॉर्म का समय वाला पहलू अहम होगा। सुंदरबन और सर क्रीक जैसे क्षेत्रों में विविध जलीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट समुद्री योजना बनानी होगी। आर्थिक यूडीए के लिए पीएम गति शक्ति को अपनाने से भारत स्मार्ट सिटी के तर्ज पर 'स्मार्ट समुद्री क्षेत्रों' का विकास कर सकता है। इससे तकनीक संपन्न समुद्री योजना बनाने में मदद मिलेगी तथा समुद्री संसाधनों का सुरक्षित और समुचित खनन हो सकेगा। इस दौरान पानी के नीचे प्रदूषण, आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन भी संभव होगा। इसके लिए सागर यानी सिक्युरिटी ऐंड ग्रोथ फॉर आल इन द रीजन को एक नए स्तर पर ले जाना होगा और यह भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अव्वल बनाएगा।

आर्थिक यूडीए के लिए गति शक्ति योजना मानव संसाधन नियोजन के लिए भी निर्देशन का काम करेगी। जरूरत इस बात की है कि नीति निर्माताओं, सेना और पुलिस में जागरूकता बढ़ाई जाए। समुद्री शोध केंद्र इस क्षेत्र में एक संसाधन केंद्र बनकर उभरा है। उसकी भूमिका का विस्तार करके तथा उसके साथ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करके क्षेत्रीय क्षमता विस्तार केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। समुद्री शोध केंद्र नवाचार के केंद्र के रूप में भी काम कर सकता है और यूडीए केंद्रित स्टार्टअप के विकास में मदद कर सकता है। यूडीए को जहां सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखा गया है वहीं इसमें आर्थिक उत्प्रेरक होने की भी संभावना है। इसी प्रकार अतीत में इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आयोगों जैसी पहल के तर्ज पर आर्थिक यूडीए के लिए गति शक्ति भी भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में ला सकती है। यूडीए में यह क्षमता है कि वह भारत की समुद्री विरासत में नई जान फूंके और आर्थिक वृद्धि तथा वैश्विक नेतृत्व का अवसर मुहैया कराए।

(लेखक भारत के पूर्व रक्षा सचिव और आईआईटी कानपुर के विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक हैं)

प्राथमिकता पर दूर हो पनडुब्बियों की कमी

भारत के जिन सैन्य अधिग्रहणों में बहुत अधिक देरी हुई है उनमें से एक है '30 वर्ष की पनडुब्बी निर्माण योजना' जिसे कैबिनेट ने 1999 में मंजूरी दी थी ताकि 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सके। नौसेना के लंबी दूरी वाले समुद्री गश्त लगाने वाले विमानों के साथ मिलकर ये पनडुब्बियां, शत्रुओं की पनडुब्बियों को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में आजादी से घूमने से रोक देंगी।

तीस वर्षीय योजना में भारत में छह पारंपरिक डिजाइन वाली पनडुब्बियां बनाने की बात शामिल है जिन्हें फ्रांसीसी, जर्मन या स्वीडिश डिजाइन पर तैयार होना है। उसके बाद छह अन्य पनडुब्बियां पूर्वी डिजाइन पर यानी रूसी, दक्षिण कोरियाई या जापानी डिजाइन पर तैयार होनी हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों से विशेषज्ञता हासिल करने के बाद भारतीय शिपयार्ड अगली 12 पनडुब्बियों को स्वदेशी ढंग से तैयार करेगा।

एक अन्य गोपनीय पहल में नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिजाइनर परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों तथा बैलिस्टिक मिसाइल युक्त परमाणु संपन्न पनडुब्बियों का एक छोटा बेड़ा बनाएंगे। ये कई सप्ताह नहीं बल्कि महीनों तक पानी में रह सकेंगी और लंबे मिशन में काम आएंगी। भारतीय नौसेना ने इनके संचालन की क्षमता विकसित करने के लिए रूस से दो बार इन्हें लीज पर लिया है। इन्हें शत्रु पनडुब्बियों और युद्धपोतों के विरुद्ध आजमाने के बजाय भारत के नाभिकीय प्रतिरोध के तीसरे स्तर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जो जलमग्न होकर काम करेगा।

इस योजना को अंतिम रूप देने के बाद भी चौथाई सदी बीत चुकी है लेकिन शुरुआती छह पनडुब्बियां भी नहीं बन सकी हैं। प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 18 पनडुब्बियां बनाने के लिए पांच साल की अवधि बची है और यह नामुमकिन प्रतीत होता है

हमारी तट रेखा 5,600 किलोमीटर है और करीब 1,800 किलोमीटर इलाका द्वीपों का है। 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) हैं। दुनिया के व्यापार का दो तिहाई इसी समुद्री इलाके से होकर गुजरता है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल एवं गैस तथा स्वेज नहर के मार्ग से जिंस और हाइड्रोकार्बन का आवागमन शामिल है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का व्यापार मलक्का की खाड़ी, सुंडा, लॉम्बॉक और ओम्बाई जलडमरूमध्य से गुजरता है जहां पोतों की नाकाबंदी की जा सकती है।

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

अगर भारत का प्रायद्वीपीय इलाका दोनों ओर उथले पानी वाला होता तो हमारी नौसेना पारंपरिक पनडुब्बियों से काम चला लेती। अरब सागर की ढाल इतनी कम गहरी है कि कराची से 40 समुद्री मील दूर सागर की तलहटी केवल 40 मीटर गहरी है। इतनी गहराई में बड़ी पनडुब्बी काम नहीं कर सकतीं। परमाणु क्षमता संपन्न 4,000 टन भारी पनडुब्बी और बड़ी पारंपरिक पनडुब्बी कराची के तट के निकट नहीं संचालित हो सकतीं। भारत की पूर्वी तट रेखा में ढाल काफी गहरा है और यह बड़ी पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहां परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियां भी संचालित हो सकती हैं जो मलक्का की खाड़ी में लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों को ऐसा करने में केवल खाद्य सामग्री और इंसानी सहनशक्ति की बाधा ही सामने आती है। एक परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी विमान वाहक युद्धक समूह का हिस्सा बनने के लिए बेहतर तैयार होती है। इससे शत्रु पनडुब्बियों से बेहतर बचाव मिलता है। समुद्री क्षेत्र में भारत की आकांक्षाओं को देखते हुए हमारे बेड़े में कम से कम 3-4 ऐसी परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियां होनी चाहिए।

अधिकांश बड़ी नौसैनिक शक्तियां मसलन फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका आदि परमाणु बेड़े को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उसकी वैश्विक पहुंच है और कई प्रकार की पनडुब्बियों का संचालन महंगा है। अमेरिका पनडुब्बी तकनीक में साझेदारी नहीं करता क्योंकि यह उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि फ्रांस और रूस केवल निर्यात के लिए पारंपरिक पनडुब्बियां बना रहे हैं जबकि उनकी नौसेनाएं परमाणु संपन्न पनडुब्बियां संचालित कर रही हैं। खरीदारों की बात करें तो जिन्हें बेहतर तकनीक वाली पनडुब्बियां चाहिए उनके लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (एआईपी) वाली गैर परमाणु प्रपल्शन सिस्टम उपलब्ध है जो पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की सुविधा देता है। इन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर नहीं आना होता।

नौसेना ने जुलाई 2021 में सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट-75 आई के अंतर्गत छह पनडुब्बियों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। डिफेंस एक्विजिशन प्रॉपोजीशन 2020 के तहत सामरिक साझेदारी के तहत खरीद के लिए चार हथियार श्रेणियों को चिह्नित किया गया: लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और सशस्त्र लड़ाकू वाहन या मुख्य युद्धक टैंक।

चूंकि प्रोजेक्ट-75 आई एक पोत निर्माण परियोजना है इसलिए पहला चरण था दो भारतीय कंपनियों का सामरिक साझेदार के रूप में चयन- मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) और लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी)। इन कंपनियों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध पेश करने को कहा गया है और इन्हें किसी सूचीबद्ध ओईएम के साथ सहयोग करना होगा। पांच चुनी हुई ओईएम हैं फ्रांस का नवल ग्रुप, जर्मनी का टिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस), रूस का रोसोबोरोनएक्सपोर्ट यानी आरओई, दक्षिण कोरिया की डेवू शिपबिल्डिंग ऐंड मरीन इंजीनियरिंग (डीएसएमई) और स्पेन की नवांतिया। इन्हें कड़ी स्वदेशी शर्तों का पालन करना होगा यानी पहली पनडुब्बी के लिए 45 फीसदी स्वदेशीकरण तथा छठी यानी अंतिम के लिए 60 फीसदी। इस परियोजना की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

सामरिक साझेदार कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए पांच विदेशी कंपनियों के चयन के बावजूद प्रभावी तौर पर निविदा के लिए दो ही प्रतिस्पर्धी थे- टीकेएमएस और डीएसएमई। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य तीन कंपनियां निविदा की शर्तें पूरी नहीं कर पा रही थीं। टीकेएमएस ने बोली में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। ऐसे में नौसेना को या तो एक वेंडर से खरीद करनी होगी या फिर निविदा में संशोधन करना होगा।

जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस को इनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि उसने 1980 और 1990 के दशक में मुंबई के मझगांव डॉक में भारत की नौसेना के लिए 209/1500 पनडुब्बियां बनाई थीं। इन पनडुब्बियों की बहुत सराहना की जाती है। ऐसे में मझगांव भारत का इकलौता डॉक है जिसे पनडुब्बी बनाने का पूरा अनुभव है। इसके अलावा दो प्रमुख पनडुब्बियां मसलन आईएनएस शिशुमार और आईएनएस शंकुश को पहले ही मझगांव डाक और टीकेएमएस द्वारा मध्यम रीफिट किया जा चुका है।

भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही टाइप 209 एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों को एचडीडब्ल्यू टाइप 214 में विकसित किया गया जो दुनिया की कई नौसेनाओं द्वारा संचालित हैं। इनमें इटली, कोरिया और तुर्की शामिल हैं। आखिर में टीकेएमएस जो डिजाइन बनाने की योजना बना रही है वह दो प्रकार के एआईपी के साथ एक अधिक लचीली पनडुब्बी डिजाइन है: फ्यूल सेल एआईपी जो कम गति पर लंबी दूरी के लिए कारगर है और दूसरा लीथियम आयन बैटरी जो उच्च गति के लिए मुफीद हैं।

हिंद महासागर के पहरेदार की भारत की भूमिका को देखते हुए पनडुब्बियों की कमी को दूर करना नई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आपका पक्ष

स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाना जरूरी

बीते दिनों दिल्ली और एनसीआर के लगभग 200 स्कूलों में बम रखने की ईमेल धमकी से सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के विद्यार्थी या उनके अभिभावक ही चिंता में नहीं पड़े बल्कि देश में शिक्षा से जुड़े सभी लोग चिंतित हो गए। हालांकि किसी भी स्कूल में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दिल्ली और एनसीआर के साथ-साथ अन्य राज्यों के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थान इससे सबक लेते हुए अपने यहां सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सीसीटीवी कैमरे हर छोटे बड़े स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में जरूरी किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को भी स्कूलों और कॉलेजों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ानी चाहिए और इनके आसपास हर समय पुलिस का पहरा हो, खासतौर पर इन संस्थाओं के खुलने और बंद होने के समय कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

चेन्नई में रविवार को नीट परीक्षा देने से पहले परीक्षा केंद्र पर छात्राओं की सुरक्षा जांच करती सुरक्षाकर्मी

न्याय व्यवस्था में सुधार जरूरी

यह हमारे देश में न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है कि न्याय पाने में लोगों को कई-कई वर्ष लग जाते हैं। जिन लोगों को जेल भेजा जाता है, उनमें से कई कई महीनों तक पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट ही कोर्ट में पेश नहीं करती। फिर कुछ मामलों में जमानतदार नहीं मिलने से भी जमानती अपराधों में व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि लंबे समय तक जेल में रहने के बद जब कोर्ट व्यक्ति को निर्दोष करार दे देता है। तब उसको बिना वजह जेल में रखे जाने वाले दुख और समाज में बदनामी का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। जेल से छूट हुए व्यक्ति को कोई भी नौकरी नहीं देता। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 8 दिन के भीतर चार्ज शीट पेश नहीं करने या जमानतदार नहीं मिलने पर व्यक्ति को स्वतः जेल से रिहा करने का नियम बनाया जाए।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

पर्यावरण हितैषी गिद्ध विलुप्ति के कगार पर

भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से चार लुप्तप्राय हैं। बियर्डेड वल्चर, सिनसेस वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, ग्रिफ्फॉन वल्चर, हिमालयन वल्चर, इंडियन वल्चर, बंगाल का गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध। गिद्धों के लिए विषमुक्त भोजन, स्वच्छ पानी, बोन चिप्स और सुरक्षा एवं आजादी के लिए तार से घेरे हुए खुली छत वाले बसेरों के माध्यम से गिद्ध फीडिंग स्टेशन बनाने की जरूरत है। गिद्धों की रक्षा में हर व्यक्ति और संस्थाओं को सहयोग के लिए आगे आना होगा ताकि गिद्धों के संरक्षण एवं पर्यावरण स्वच्छता के लाभ के साथ गिद्धों की संख्या में वृद्धि कर उनके आवासीय स्थल सुरक्षित किए जा सकें। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि गिद्धों की संख्या में कमी का कारण प्रदूषण, सिकुड़ते जंगल, विषैले पदार्थ खा लेने के चलते इनका जीवन प्रभावित हुआ है। पर्यावरण हितैषी गिद्ध धरती पर जहां संक्रमण रोकते हैं वहीं स्वच्छता में हमारे सहयोगी रहे हैं। गिद्धों के हितों का ध्यान रखा जाए ताकि गिद्ध विलुप्ति के कगार पर नहीं पहुंचें।

संजय वर्मा, धार

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वैर पर भारतीय-अमेरिकी समुदाय की महिलाएं शनिवार (अमेरिकी समयानुसार) को 'साड़ी गोज ग्लोबल' कार्यक्रम के तहत साड़ी परिधान में नजर आईं। कार्यक्रम में 9 देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, त्रिनिदाद और गुयाना की लगभग 500 महिलाएं शामिल हुईं।

कोई भी सुधार तभी हुआ है, जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति-रिवाज स्वयं तोड़ डाले हैं।

- महात्मा गांधी

मोदी की स्वीकारोक्ति

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

झूठ को सामने रखकर और कांग्रेस के घोषणापत्र की सच्चाई चुनावी बहस में लाने में सक्षम बनाकर तथा भाजपा के घोषणापत्र का कोई संदर्भ न देकर, मोदी जी ने स्टालिन का समर्थन किया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस का घोषणापत्र 2024 के लोकसभा चुनावों का असली नायक है।

इस लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र 2019 से ही तैयार हो रहा था। राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से यह देखने और जानने-समझने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ऐतिहासिक पदयात्रा की थी कि आम लोग कैसे और किन परिस्थितियों में रह रहे हैं और उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। उदयपुर सम्मेलन एक ऐसा अवसर बना था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तीन दिनों तक एक साथ रहने और देश के सामने आने वाली चुनौतियों और उन पर संभावित प्रतिक्रियाओं को लेकर विचार-विमर्श करने का मौका मिला था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआइसीसी) के रायपुर सम्मेलन के बाद पार्टी नीतियों का एक ऐसा व्यापक और विश्वसनीय मंच तैयार करने में सक्षम हुई थी, जो राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय चुनावों में भी भाजपा को चुनौती दे सकता है।

नव संकल्प आर्थिक नीति की रचना उदयपुर में की गई थी। 'केंद्र में गरीब' विषय पर रायपुर में विचार-विमर्श किया और उसे अपनाया गया था।

कांग्रेस का घोषणापत्र 5 अप्रैल को जारी हुआ था, जिसे 'न्याय पत्र' नाम दिया गया। इस दस्तावेज के छियालीस पृष्ठों को जो एक सूत्र पिरोता है, वह है 'न्याय', जिससे लोगों के एक बड़े वर्ग को वंचित कर दिया गया था। 'न्याय' शब्द में सामाजिक न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय और श्रमिकों के लिए न्याय शामिल हैं। लोगों के बड़े वर्ग के साथ भेदभाव किया गया और उन्हें देश की तेज या धीमी विकास गाथा में भागीदारी के उचित अवसर से वंचित किया गया। कांग्रेस का घोषणापत्र 'सबका साथ सबका विकास' के नारे पर से पर्दा हटाने और देश के शासकों को आईना दिखाने वाला है। इसने समता और न्याय के साथ वृद्धि और विकास का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांग्रेस के घोषणापत्र को 2024 के चुनावों का 'हीरो' बताया।

शुरू में, मोदी जी और भाजपा ने कांग्रेस के घोषणापत्र को नजरअंदाज करने का फैसला किया। मीडिया ने भी इस दस्तावेज पर बहुत कम ध्यान दिया। मगर जैसे-जैसे इसके अनूदित संस्करण राज्यों तक पहुंचे, और उम्मीदवारों और प्रचारकों ने गांवों और कस्बों में इसके मुख्य संदेश पहुंचाए, कांग्रेस का घोषणापत्र लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। (पढ़ें : कांग्रेस के घोषणापत्र का पुनर्लेखन, जनसत्ता, 28 अप्रैल, 2024)

पांच अप्रैल के नौ दिन बाद भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस मोदी-पूजक दस्तावेज के गुणों की प्रशंसा खुद मोदी जी ने भी नहीं की, जिसका शीर्षक है 'मोदी की गारंटी'। सात दिन बाद, 21 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। उसकी 'खुफिया जानकारी' जाहिर तौर पर भाजपा के लिए बुरी खबर थी। यह स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं ने घोषणापत्र में किए गए 'वादों' के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वोट दिया है, जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में 'गारंटी' के लिए वोट किया था। इससे मोदी को एक रास्ता मिल गया और 21 अप्रैल को उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली।

भाजपा ने अपने नेताओं और सदस्यों के लिए जो पटकथा तैयार की, उससे शायद 'गोएबल्स' को गर्व महसूस हुआ होगा। वह पटकथा थी: झूठ, और ज्यादा झूठ और उससे भी ज्यादा झूठ; अगर सत्य कहीं झूठ का प्रतिकार करता हो, तो सत्य को नजरअंदाज कर दो। यहां पिछले चौदह दिनों में फैलाए गए झूठों का एक नमूना पेश है:

झूठ: कांग्रेस के घोषणापत्र पर मुसलिम लीग की छाप है।

सच्चाई: छियालीस पन्नों में से किसी पर भी 'मुसलिम' शब्द नहीं आया है। अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया गया है और कांग्रेस ने वादा किया है कि 'भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान के तहत जो मानव और नागरिक अधिकार दिए गए हैं, कांग्रेस उन अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का वचन देती है।' एससी, एसटी और ओबीसी के कई संदर्भ हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक समुदाय का कोई संदर्भ नहीं है।

झूठ: अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो शरीअत कानून वापस लाएगी।

सच्चाई: घोषणापत्र में कहा गया है, 'हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।'

झूठ: कांग्रेस के घोषणापत्र में मार्क्सवादी और माओवादी आर्थिक सिद्धांतों की वकालत की गई है।

सच्चाई: दस पृष्ठों के अर्थव्यवस्था वाले खंड के परिचय में कांग्रेस ने कहा है: कांग्रेस की आर्थिक नीति पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है। 1991 में कांग्रेस ने उदारीकरण के युग की शुरुआत की और देश को नियामक निरीक्षण के साथ एक खुली, स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। देश को धन-सृजन, नए व्यवसायों और उद्यमियों, एक विशाल मध्यवर्ग, लाखों नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में महत्त्वपूर्ण नवाचारों और निर्यात के मामले में भारी लाभ मिला। लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। हम एक खुली अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जिसमें आर्थिक विकास निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होगा और एक मजबूत और व्यावहारिक सार्वजनिक क्षेत्र का पूरक होगा।

झूठ: चुनाव जीतने पर कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म कर देगी।

सच्चाई: घोषणापत्र में कहा गया है कि 'कांग्रेस गारंटी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की तय पचास फीसद की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसद का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा। हम एक वर्ष की अवधि के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर सभी लंबित रिक्तियों को भर देंगे। एससी, एसटी और ओबीसी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए और भी कई वादे किए गए हैं।

झूठ: कांग्रेस विरासत कर लगाएगी।

सच्चाई: कराधान और कर सुधारों पर 12-बिंदु अनुभाग में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष कर संहिता बनाने का वादा किया है; पांच वर्षों के लिए स्थिर व्यक्तिगत आयकर दरें बरकरार रहेंगी; पांच फीसद पर उपकर और अधिभार की सीमा; जीएसटी का दूसरा चरण लागू होगा; और एमएसएमई और छोटे खुदरा व्यवसायों पर करों का बोझ कम करेंगे। इसमें विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है।

झूठ को सामने रखकर और कांग्रेस के घोषणापत्र की सच्चाई चुनावी बहस में लाने में सक्षम बनाकर तथा भाजपा के घोषणापत्र का कोई संदर्भ न देकर, मोदी जी ने स्टालिन का समर्थन किया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस का घोषणापत्र 2024 के लोकसभा चुनावों का असली नायक है।

थके-हारे मतदाता

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

दोनों तरफ से मतदाताओं को डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन जमीन पर यथार्थ यह है कि मतदाता कहते हैं कि उनकी नजर में न लोकतंत्र को खतरा दिखता है न संविधान के समाप्त होने का। अपना वोट जब देने जाएंगे तो यही सोच कर कि उनके लिए किस पक्ष ने ज्यादा काम किया है और भविष्य में कौन उनके लिए ज्यादा काम करने वाले हैं।

दोनों पक्ष कहते हैं कि ये आम लोकसभा चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी की नजर में विशेष इसलिए है कि 'इंडी गठबंधन' जीतेगा तो देश को ऐसी सरकार मिलेगी जो माताओं, बहनों के मंगलसूत्र और स्त्रीधन तक छीनने का काम करेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि ये आम लोकसभा चुनाव नहीं है, विशेष है, इसलिए कि अगर मोदी तीसरी बार जीतते हैं तो न लोकतंत्र रहेगा और न संविधान। दोनों तरफ से मतदाताओं को डरा कर उनका वोट हासिल करने का काम हो रहा है। असलियत यह है कि मतदाता आज इतने भोले नहीं हैं कि इस तरह के प्रचार के शिकार बन जाएं।

मतदान का दूसरा दौर समाप्त होने के बाद क्या कहा जा सकता है इस चुनाव के बारे में? यहां कहना जरूरी है अपनी तरफ से कि मैं जो भी कहूंगी, गालियां पड़ेंगी दोनों तरफ से, इसलिए कि दोनों पक्षों ने सोशल मीडिया पर ऐसे लोग बिठा रखे हैं जो राजनीति के बारे में इतना कम जानते हैं कि सोचते हैं कि विश्लेषण करने वाले निष्पक्ष हो नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के प्रचार के बारे में कुछ कहती हूं तो पीछे पड़ जाते हैं उनके ऐसे समर्थक जो मुझ पर गांधी परिवार से 'नफरत' करने का आरोप लगाते हैं। मोदी के प्रचार के बारे में कुछ कहती हूं तो पीछे पड़ जाते हैं मोदी भक्त जो मुझ पर यही आरोप लगाते हैं। सो, आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट करना चाहती हूं कि नफरत के आधार पर नहीं किया जाता है राजनीतिक विश्लेषण। इतना कठिन क्यों है इस बात को समझना?

अब सुनिए मेरी राय में चुनाव कैसी शक्ल ले चुका है। पहली बात यह कि मुझे लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव न रहकर अमेरिकी किस्म का राष्ट्रपति चुनाव बन गया है, जिसमें लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच हो रही है। राहुल की बहन प्रियंका के अलावा एक भी दूसरे कांग्रेस राजनेता का कोई महत्त्व नहीं दिख रहा है। बड़ी आम सभाओं को संबोधित यही दोनों बहन-भाई कर रहे हैं और दोनों के भाषणों में निशाना बनते हैं मोदी। कहते हैं इन दिनों कि मोदी इसलिए डर गए हैं कि जानते हैं कि 400 पार तो दूर की बात, उनको 180 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं इस बार। पिछले सप्ताह राहुल गांधी ने अपना नामांकन रायबरेली से भरने से पहले कहा कि उनका अपना अनुमान है कि मोदी 150 पर रुक जाएंगे। और चार जून को जब कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में तो हर गरीब महिला के बैंक खाते में 'खटाखट' पहुंच जाएंगे एक लाख रुपए। हर शिक्षित बेरोजगार को कांग्रेस पार्टी देगी पहली नौकरी 'अप्रेंटिसशिप' योजना द्वारा एक साल के लिए।

दूसरी तरफ हैं मोदी और अमित शाह, जिनको सोशल मीडिया पर 'मोशाह' कहा जा रहा है। इनके प्रचार में भी कांग्रेस के 'शहजादे' को मुख्य निशाना बना रखा है। याद दिलाया जा रहा है कि जब इनके परिवार के हाथों में थी देश की बागडोर तो भारत को लूटने का काम ही किया गया था। यही लूट दोबारा होने वाली है और इस बार जो संपत्ति लोग बनाते हैं अपने जीवन में उसका आधा हिस्सा कांग्रेस की सरकार लूटने वाली है उनके मरने के बाद। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से मतदाताओं को डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन जमीन पर यथार्थ यह है कि मतदाता कहते हैं कि उनकी नजर में न लोकतंत्र को खतरा दिखता है न संविधान के समाप्त होने का। अपना वोट जब देने जाएंगे तो यही सोच कर कि उनके लिए किस पक्ष ने ज्यादा काम किया है और भविष्य में कौन उनके लिए ज्यादा काम करने वाले हैं।

यहां यह कहना जरूरी है कि जब मैं घूमने निकलती हूं ग्रामीण क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं। ऐसा लगता है जैसे पिछले दस सालों में कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने पार्टी की जड़ें दोबारा मजबूत करने के लिए कोई मेहनत नहीं की है। सेवा दल जैसी संस्थाएं जो कभी कांग्रेस के प्रचार में बहुत काम आया करती थीं, अब तकरीबन गायब हो गई हैं। इसलिए अगर राहुल गांधी की बात सही साबित होती है तो सारा श्रेय उनको जाएगा और उनकी बहन को। सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस छाई हुई है मोदी से भी ज्यादा। लेकिन जमीन पर नहीं।

भारतीय जनता पार्टी को अगर तीसरी बार बहुमत मिलता है लोकसभा में तो उसका श्रेय जाएगा मोदी को ही। इसलिए कि मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं इस चुनाव में। गांवों में जो विकास के कार्य देखने को मिलते हैं उनका सारा श्रेय लोग देते हैं मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। राजस्थान के कुछ इलाकों में भाजपा की तरफ से ऐसे लोग खड़े किए गए हैं जिन्होंने संसद में पहुंचने के बाद लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वे जीत सकते हैं दोबारा मोदी के नाम पर।

तो क्या मोदी का जादू फिर से चलने वाला है? यहां निजी तौर पर कहना चाहूंगी कि मोदी बेशक इस दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन वह 'हर हर मोदी, घर घर मोदी' वाली बातें जो 2019 में सुनने को मिलती थीं, इस बार नहीं सुनाई देती हैं। मतदाता थके-हारे से लगते हैं इस बार। फिलहाल महाराष्ट्र में हूं, जहां गर्मी इतनी है कि बाहर जाना मुश्किल है और इस गर्मी में पानी की इतनी बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कि कुछ गांव मतदान नहीं करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जिस देश में पीने के लिए पानी ही न मिले, वहां कैसे कोई देख सकता है क्षितिज पर विकसित भारत के आसार।

बौद्धिकता बनाम उपभोक्तावाद

संदर्भ

राकेश सिन्हा

मस्तिष्क उत्पादक कम, उपभोक्ता अधिक बन गया है। वह सतह से नीचे जाकर चीजों का जानने-परखने की क्षमता खो रहा है, मनोरंजन की आवश्यकता उसके मस्तिष्क की भूख शांत करने के लिए अनिवार्य पहलू बन जाती है। उस मनोरंजन में तात्कालिकता तो है, पर दीर्घकालिकता नहीं है। भौतिकता ने मस्तिष्क को विलासी उपभोक्ता बना दिया है।

पहले की तुलना में पुस्तक पढ़ने की लालसा और क्षमता दोनों घटी है। इसके बावजूद 2010 में तेरह करोड़ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। अकेले भारत में 2022 में नब्बे हजार शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर अधिक समय गुजारती है। कम शब्दों में व्यक्त विचार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती हैं। इसी को विमर्श मान लिया जाता है। मन हल्के तरह से हल्की भाषा में बोलने और लिखने की आदत के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। यह वैश्विक प्रवृत्ति है। इसके कारण और परिणामों पर चिंता की जगह चिंतन आज के दौर में उपलब्धि मानी जाएगी।

विज्ञान अपनी तरह से उन्नति कर रहा है। उसकी प्रगति में मनुष्य को श्रमजीवी से तकनीकजीवी बनाना लक्ष्य है। शहरों-महानगरों में आर्थिक संपन्नता और तकनीकी उपलब्धता ने मनुष्य को शारीरिक श्रम से दूर किया है। इसका फलक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। डर है कि मनुष्य तकनीक की तरह और तकनीक मनुष्य की तरह न व्यवहार करना शुरू कर दे। यह प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान अपने आप में स्वायत्त एवं संप्रभु है। आज ऐसा ही लग रहा है। दूसरे क्षेत्रों, आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन आदि में प्रगति का सूचकांक कम होने से उनका प्रभाव घटा है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी को पुरानी संरचना और कर्मकांड में बांधकर रखने का काम उन्हें भौतिकवाद में मुक्ति दिखाता है। इसे भारतीय दर्शन में चार्वाक कहा गया। उदाहरणार्थ, अमेरिका में चर्च की सदस्यता 1937 में 73 फीसद थी, जो 2020 में घटकर 47 फीसद रह गई है। यूरोप और अन्य इसाई भूभागों में भी इस प्रवृत्ति का बोलबाला है। नौजवानों को नई खोज, नए उपभोग की सामग्री उत्तेजित करती है। विज्ञान की सार्थकता समाज के उत्थान में है, पर विज्ञान भौतिकता को बढ़ा कर मनुष्य के मस्तिष्क को सामाजिक स्तर पर बंजर बना रहा है। इसलिए अध्यात्म, दर्शन, संस्कृति की भूमिका अहम हो जाती है।

जब अध्यात्म मानव जीवन मूल्यों को दर्शन के रास्ते परिभाषित करता है और उसे उस विचार को पढ़ने, सुनने, आत्मसात करने में व्यक्ति अपना सशक्तीकरण देखता है, तब आध्यात्मिक दर्शन की चौहद्दी फैलती जाती है। यही मस्तिष्क सृजनकर्ता बनता है। इसे मस्तिष्क की उत्पादकता भी कहते हैं। इसमें मानसिक श्रम और समय दोनों की आवश्यकता होती है। कर्मकांड से बंधी संस्थाएं सृजन का कार्य नहीं कर पाती हैं। मस्तिष्क बंधक बना रहता है। भारत की स्थिति भिन्न रही है। भारतीय दर्शन को अध्यात्म से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अध्यात्म कर्मकांड को आवश्यक मानता है, अनिवार्य नहीं। भारतीय परिवेश में जब व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना पैदा होती है, तब वह उसे अपने अधिनायकवाद में तब्दील कर अंतिम सत्य या पथ घोषित नहीं करता है। यही इसकी खूबी और खुशबू दोनों है। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य अपने ज्ञान को मिल रही चुनौती से न पीछे हटते थे, न ही उसे दार्शनिक हिंसा मानते थे।

बौद्धिकता और दर्शन की सृजनशीलता व्यक्तिगत होती है। इसका दायरा भी सीमित होता है। पर यह आम लोगों को सोचने, समझने, उलझने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसीलिए संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। शंकराचार्य ने चार धामों की स्थापना की। प्रत्येक धाम अपने आप में स्वायत्त है। ये धाम मूलतः दर्शन और मूल्यों के सृजन के पीठ के रूप में थे, जिसमें संस्कृति के प्रवाह को संदर्भित करने की क्षमता होती थी। आठवीं शताब्दी में स्थापित ये धाम इक्कीसवीं शताब्दी में अपनी कितनी सृजनशीलता बनाए हुए हैं, यह अध्ययन का विषय है। महाराष्ट्र में तेरहवीं शताब्दी में समाज परिष्कार की मौलिक परंपरा कीर्तन (भजन मंडली) शुरू हुई थी। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव के प्रवचनों को नृत्य, संगीत, कथा वाचन एवं अभिनय के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था।

बौद्ध विद्वानों के बीच सामयिक प्रश्नों के साथ उसकी सार्थकता को लेकर तीन प्रसिद्ध विशाल परिषदें- राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में दो हजार वर्ष पूर्व हुई थीं। ये विचार विनिमय एकांगी नहीं होते थे। समाज, संस्कृति, प्रकृति, विज्ञान, मनुष्य सभी पक्षों को विचारणीय माना जाता था। ये यही मूल दर्शन अंततः साहित्य, समाजशास्त्र, शासन कला और राजनीति को प्रभावित करता था। यह इस बात का भी सूचक है कि संस्थानों का स्वस्थ, स्वायत्त होना और स्वतंत्र विचार-विमर्श का केंद्र होना कितना आवश्यक है। वे मानव की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। प्रगति का तब तात्पर्य भौतिकता का ऐश्वर्य नहीं, समष्टि को प्रभावित और परिष्कृत करने वाले दर्शन का निर्बाध प्रवाह है। उपनिषद तभी तो चिरंजीवी हुआ है। प्रकारांतर से मस्तिष्क उत्पादक कम, उपभोक्ता अधिक बन गया है। वह सतह से नीचे जाकर चीजों का जानने-परखने की क्षमता खो रहा है, मनोरंजन की आवश्यकता उसके मस्तिष्क की भूख शांत करने के लिए अनिवार्य पहलू बन जाती है। उस मनोरंजन में तात्कालिकता तो है, पर दीर्घकालिकता नहीं है। भौतिकता ने मस्तिष्क को विलासी उपभोक्ता बना दिया है। यह व्यक्ति की उदात्तता को न सिर्फ कम कर रहा है, उसे सीमित सामाजिकता में जीने के लिए बाध्य कर रहा है। एक भिन्न प्रकार का व्यक्तिवादी चरित्र विकसित हो रहा है। विज्ञान और भौतिकता की सांठगांठ और भी प्रतिकूलता को जन्म दे रही है। विरासत की चादर ओढ़कर हम अपने कमजोर वर्तमान और बौद्धिक चरित्र को नहीं छिपा सकते है। प्राचीनता की उपयोगिता और उसके प्रभाव की अपनी सीमा है।

दावे और इरादे

बाखबर

सुधीश पचौरी

इसी क्रम में एक दिन चुनाव आयोग ने पहले दो चरणों में हुए मतदान फीसद के आकड़ों को 'अद्यतन' कर नए आंकड़े दिए तो मतदान इतना कम भी न दिखा, जितना बताया जाता रहा। मगर नए आंकड़ों पर चर्चा किसी चैनल ने न कराई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम 'ओके' है... बाकी मुद्दे आयोग के हवाले। कुछ देर तक एक मायूसी-सी हवा में छाई रही। फिर विपक्ष के एक रणबांकुरे ने यह कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन लड़ाई लंबी है। दूसरे विपक्ष के नेता ने कहा कि इस चुनाव में 'मैच फिक्सिंग' कर रहे हैं। एक नेत्री जी भी कहिन कि इन्होंने पहले ही गड़बड़ कर रखी है, वरना कैसे कह सकते हैं कि चार सौ पार..! फिर चार सौ पार की व्याख्या की जाती रही कि चार सौ पार इसलिए, ताकि भाजपा संविधान बदल सके।

इसके बाद तो 'आरक्षण बरक्स आरक्षण' जम कर हुआ। इसी कारण 'कोटा बरक्स कोटा युद्ध' कई दिन चैनल चर्चा में छाया रहा। एक विपक्षी कहिन कि चार सौ पार लाए तो ये आरक्षण हटा देंगे। उधर 'चार सौ पार' वाले कहिन कि कांग्रेस आई तो अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को काटकर उसकी जगह धार्मिक आधार पर मुसलिम अल्पसंख्यक को आरक्षण दे देगी, जबकि धार्मिक आधार पर कोटा देना गैरकानूनी होगा। जब 'कोटा बरक्स कोटा' खूब हो चुका तो 'चार सौ पार' वाले मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि कोटा भीतर मुसलिम अल्पसंख्यक को कोटा नहीं देंगे... 370 नहीं हटाएंगे..!

फिर एक बार और स्वयं मोदी ने साफ किया कि कांग्रेस झूठ फैला रही कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आज बाबा साहब आ जाएं तो वे भी संविधान नहीं बदल सकते। इसके अलावा एक दिन एक चैनल पर मोदी ने लंबा साक्षात्कार देकर कांग्रेस के घोषणापत्र के एलानों की धज्जियां बिखेरीं। साथ ही अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। फिर अमित शाह ने भी एक रैली में साक्षात्कार देते हुए बहुत से आरोपों का जवाब दिया। इसी बीच भाजपा के एक नेता ने साफ किया कि पहले दो चरण में भाजपा 2.0 से आगे है। फिर एक चैनल पर भाजपा के एक बड़े नेता की मार्फत लाइन आई कि 4 जून को दोपहर 12.30 पर 400 पार।

इसी क्रम में एक दिन चुनाव आयोग ने पहले दो चरणों में हुए मतदान फीसद के आकड़ों को 'अद्यतन' कर नए आंकड़े दिए तो मतदान इतना कम भी न दिखा, जितना बताया जाता रहा। मगर नए आंकड़ों पर चर्चा किसी चैनल ने न कराई। नए आंकड़ों पर विपक्ष के नेता सिर्फ इतना ही कह सके कि आयोग को अधिक पारदर्शी होना चाहिए।

फिर एक दिन कांग्रेस को बड़ा झटका दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने दिया और दूसरा झटका इंदौर के कांग्रेसी उम्मीदवार ने आखिरी दिन अपना नाम वापस लेकर दिया। यही नहीं, उम्मीदवार भाजपा के एक नेता के साथ जाता दिखा। फिर भी कांग्रेस में कहीं कोई अफसोस और आह-कराह नहीं।

फिर आया मारिया जी का बयान कि 'वोट जिहाद' करें... जो मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं, उनका हुक्का-पानी बंद करें। इसे देख एक एंकर ने कटाक्ष किया कि अब तो साफ है कि कुछ मुसलमान भाजपा को भी वोट करते हैं। भाजपा को मुंहमांगी मुराद मिली। उसके प्रवक्ता तुरंत हमलावर कि ये वही 'जिहादी मानसिकता' है, जिसने देश का बंटवारा कराया। एक एंकर ने जब एक मुसलिम विद्वान से 'वोट जिहाद' का मतलब पूछा तो वे बोले कि इसका मतलब है मुसलमान अधिक संख्या में वोट डालने आएं। इसके बाद चर्चा में 'ध्रुवीकरण' छाया रहा। विपक्षी कहते कि भाजपा ध्रुवीकरण करती है तो भाजपा का जवाब आता कि कांग्रेस तो ध्रुवीकरण की मास्टर है। वह तो 'कोटा में कोटा' काटकर अल्पसंख्यकों को देती है।

और फिर एक दिन आया एक 'डीपफेक' यानी 'जाली वीडियो', जिसने गृहमंत्री से वह कहलवाया जो उन्होंने कहा नहीं था। एक चैनल ने 'असली' और 'डीप फेक' को अलग-अलग बजाकर साफ किया कि गृहमंत्री ने तो कहा था कि वे एससी-एसटी, ओबीसी आरक्षण को काटकर अल्पसंख्यकों को दिए जाते आरक्षण को हटाएंगे, जबकि 'डीपफेक' वाला वीडियो बजाता रहा कि वे एससी-एसटी आरक्षण को हटाएंगे। इसके बाद 'डीपफेक' पर केस हुआ। जांच जारी!

इसके बाद आई पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के सांसद पौत्र प्रज्वल रेवन्ना के 'वीडियो' की सनसनीखेज कहानी और उसके विदेश भाग जाने की खबर। इस पर विपक्ष बम-बम कि सदी के सबसे बड़े घोटाले पर केंद्र क्यों सोया रहा? उसे क्यों भागने दिया? भाजपा ने तुरंत साफ किया कि उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं। वह जेडीएस का है। फिर तीन महीने से वीडियो की खबर राज्य को थी, तब उसने कुछ क्यों नहीं किया।

अंततः शुक्रवार की सुबह खबर दी गई कि राहुल रायबरेली से नामांकन भरेंगे, जबकि अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा लड़ेंगे। प्रियंका प्रचार करेंगी। कई एंकर कहे कि ये फैसला पहले भी हो सकता था। इस हिचक को देख अमित शाह ने चुटकी ली कि कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है। एक चैनल ने लाइन दी: अमेठी से डर... इसलिए रायबरेली की डगर!

नई दिल्ली

www.readwhere.com

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 6 मई 2024

हकीकत नहीं बदलेगी

पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा पर कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेपाल सरकार ने सौ रुपये के नए नोट पर इन विवादित क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा छापने का फैसला किया है, वह वाकई चौंकाने वाला है।

संबंधों में उतार-चढ़ाव | नेपाल भारत के सबसे करीबी पड़ोसी देशों में शामिल है। इसकी 1850 किलोमीटर से भी लंबी सीमा भारत के पांच राज्यों से मिलती है। दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों की भी जड़ें काफी गहरी हैं। बावजूद इसके, पिछले कुछ समय से दोनों देशों के संबंधों में खासा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

नेपाल ने फिर छेड़ा सीमा विवाद

तीन क्षेत्रों पर विवाद | अगर सीमा संबंधी इसी मसले को देखा जाए तो चार साल पहले दोनों देशों के बीच यह मुद्दा काफी गरमा गया था। साल 2020 में तत्कालीन केपी ओली सरकार ने जब देश का नक्शा अपडेट किया तो उसमें तीन क्षेत्र– लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी – नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाए गए थे।

संवाद बंद | मामला तब और भड़का जब भारत ने 8 मई 2020 को लिपुलेख होते हुए मानसरोवर की ओर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताते हुए भारत के इस कदम पर इस पर कड़ी आपत्ति की, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर जाती हुई यह सड़क पूरी तरह भारत के इलाके में पड़ती है। उस वक्त नेपाल सरकार ने नक्शे में बदलाव को मजबूती देने के लिए इसके पक्ष में संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किया था। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों देशों में अस्थायी तौर पर संवाद बंद कर दिया गया।

साझा प्लैटफॉर्म | लेकिन ऐसे विवाद इस तरह के माहौल में नहीं सुलझाए जा सकते। जल्दी ही दोनों पक्षों को इसका अहसास हुआ और इस मसले को एक साझा प्लैटफॉर्म पर धीरे-धीरे बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। यह प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अचानक एकतरफा ढंग से किया गया यह फैसला स्वाभाविक ही चौंकाता है।

आम सहमति नहीं | गौर करने की बात यह है कि नोट पर नक्शा छापने के फैसले पर नेपाल के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन पर क्षेत्रों पर नेपाल के दावों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं हुई है, उन्हें देश की करंसी पर छापने का फैसला कहीं जल्दबाजी न साबित हो।

सर्वश्रेष्ठ विकल्प | बहरहाल, जहां तक सीमा संबंधी मतभेदों के सवाल हैं तो भारत स्पष्ट कर चुका है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। इस विवाद को निपटाने की जो प्रक्रिया दोनों देशों ने आपसी सहमति से तय की है, उसे आगे बढ़ाते हुए किसी सहमति पर पहुंचना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।

चक्र-व्यू

बाग बचे ना आम

राहुल पाण्डेय

सस्ते का जमाना था। बाबा ने इलाहाबाद रोड के किनारे आम के तीन पेड़ किराये पर ले रखे थे। सरकार सड़क के किनारे लगे फलदार पेड़ों को उनके सीजन में किराये पर चढ़ाती रही है। पता नहीं, अब भी ये सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। तब आम के एक पेड़ का किराया दस रुपये के आसपास पड़ा था। फल से लदा पेड़ वैसे ही रखवाली मांगता है, और कहीं वह किसी सड़क के किनारे हो, तब तो उसकी रखवाली एकदम छोटे बच्चे की तरह करनी पड़ती है। अब दिन हो या रात, वहीं पेड़ के नीचे बाबा, वहीं उनकी खाट। सड़क किनारे चलने वालों की क्या कहिए, खुद हमें उस पेड़ के आम को हाथ ना लगाने दें। उन्हें इंतजार था सारे आमों के पकने का। गरमी बहुत थी। लेकिन गरमी भी आम के पेड़ के नीचे पहुंचकर थोड़ा सुस्ता लेती थी। बाबा तो पहले ही साम, दाम और आम छोड़कर निकल लिए, इस बार गांव गया तो पता चला कि उनके किराये के पेड़ भी निकल लिए। चाचा ने बताया कि बेचारे सूख गए थे, सरकार ने कटवाकर अपनी कचहरी का दरवाजा बनवा लिया होगा! या शायद कुर्सी!

कल बड़ी बहन अंशू ने कहा कि इस बार फिर से वही गरमी की छुट्टियों की बीती याद को जीते हैं, चलो गांव चलते हैं। गांव चलेंगे, कच्चे आम की छिछली बनाएंगे, नमक-मिर्च लगाएंगे और चाट-चाट के खाएंगे। मैंने पूछा, किसके गांव जाओगी? तुम्हारे गांव में बाग बचे हैं। बोली, क्या हुआ जो मेरे गांव में बाग नहीं बचे, बड़ी मौसी के गांव में तो बचे हैं। मैंने बताया कि बाग तो वहां भी नहीं बचे। आम के पेड़ तो छोड़ो, बाग में सबसे किनारे कैथा का जो पेड़ था, अब तो वो भी नहीं रहा। बाग बन गया खेत और खेत में बो दिया गया है मिर्चा। ना खट्टा बचा है, न मीठा। गांव में अब सिर्फ मिर्च बची है, चलना हो तो चलो- चबाकर आएं। फिर उसने ननिहाल वाले गांव चलने को बोला, मगर बाग तो वहां भी नहीं बचे।

मेरे गांव का पूछा, तो वहां का तो मैंने पहले ही बता दिया कि बाग तो बाग, सड़क किनारे के भी पेड़ नहीं बचे हैं। बेचारी का मन जैसे चुचका आम, वही वाला, जो लू लगने से चीमड़ जैसा दिखता है। अब जब बाग ही नहीं बचे तो आम से भरा मन तो पिचक जाएगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात बस एक ही है कि बाग नहीं बचे। बल्कि न बाग बचे, न बाग लगाने वाले बचे। जाने कितने साल हुए, किसी को यूं ही पेड़ लगाते नहीं देखा। शायद कुछ दशकों बाद कहना पड़े कि जाने कितने साल हुए, किसी को यूं ही आम खाते नहीं देखा।

एकदा

प्रभु का बंदा

गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्य मरदाना के साथ विंध्याचल की ओर जा रहे थे। एक दिन की घटना है। मरदाना को वन्य जाति के लोग पकड़कर अपने साथ ले गए। वन्य जातियों में उन दिनों हर अष्टमी तिथि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि देने की प्रथा थी। इसी उद्देश्य से वे मरदाना को एक गुफा में ले गए, जहां भैरवी देवी का मंदिर था। वन्य जाति के लोगों ने उन्हें देवी के सम्मुख खड़ा कर रस्सी से बांध दिया और ढोल बजाते हुए नाचने लगे। नाच-गाना समाप्त होने पर उन्होंने मरदाना को मुक्त कर दिया। अब पुजारी उनके सामने बरछी लेकर आया। वह उन पर वार करने ही वाला था कि एक शांत स्वर सुनाई दिया, वाहे गुरु! एक अनजान स्वर सुनते ही पुजारी वहीं का वहीं रुक गया। वह आवाज गुरु नानकदेव की थी। वह प्रिय शिष्य मरदाना को तलाशते उस गुफा में पहुंचे तभी यह दृश्य देखकर उनके मुंह से यह आवाज निकली। सरदार की नजर नानकदेव पर पड़ी, तो वह कड़क कर बोला, 'कौन हो तुम?' नानकदेव ने शांत स्वर में कहा, 'तुम्हारे ही जैसा प्रभु का एक बंदा।' सरदार बोला, 'मगर हमें तो राक्षस कहा जाता है।' गुरु ने उसके शरीर पर स्नेहिल स्पर्श करते हुए कहा, 'तुम राक्षस नहीं हो। तुम हो तो मानव, पर तुम्हारे कार्य अवश्य राक्षसों जैसे हैं।' गुरुदेव ने प्रश्न किया, 'क्या तुम्हारी यह देवी किसी मृतक के प्राण वापस दे सकती है?' सरदार ने उत्तर दिया, 'नहीं।' 'तो फिर किसी के प्राण लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? मनुष्य को किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए।' गुरु नानक देव की शांत वाणी ने उन लोगों पर जैसे जादू का सा असर किया। वे सब उनके सामने नतमस्तक हो गए और आगे कभी नर बलि न देने की प्रतिज्ञा की।

Subrata Dhar

संकलन : **सुभाष चन्द्र शर्मा**

शुरुआती दोनों चरणों की वोटिंग में मत प्रतिशत कम रहा, लेकिन यह उतनी असामान्य बात नहीं

चुनाव में अब तक क्यों पड़े कम वोट

उमेश चतुर्वेदी

पहले और दूसरे दौर में कम मतदान के मद्देनजर यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या राजनीति और राजनीतिक तंत्र को लेकर हमारा समाज उदासीन होता जा रहा है। क्या लोगों में यह सोच गहरी हो रही है कि राजनीति चाहे इधर की हो या उधर की, लगभग एक जैसी ही है?

साक्षरता चार गुना हुई | माना जाता रहा है कि जैसे-जैसे शिक्षा का फैलाव बढ़ता है, वैसे ही वैसे लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी भी बढ़ती जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो स्वाधीन भारत की 77 साल की यात्रा में साक्षरता दर चार गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब करीब 18% लोग ही साक्षर थे। आज करीब तीन चौथाई भारत शिक्षित है। ऐसे में मतदान में लोगों की भागीदारी काफी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वह घटती दिख रही है।

चुनाव आयोग के प्रयास | मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। हर चुनाव में आयोग मशहूर सिने और टीवी हस्ती को अपना ब्रैंड अंबैसडर बनाता है, उनके जरिए मतदान की अपीलें करता है। इस बार भी आयोग ने ऐसा किया। राजनीतिक दल भी अपने समर्थक मतदाताओं को घरों से बाहर लाकर वोट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी लोग वोटिंग के लिए उत्साह नहीं दिखा रहे तो यह फिक्र की बात है। यह देखना चाहिए कि चूक कहां हो रही है।

कम वोटिंग की संभावित वजह
- मोदी की जीत तय लगना
- राजनीति से उम्मीद कम होना
- कार्यकर्ताओं में उत्साह घटना

मोदी फैक्टर | कम मतदान को लेकर कई तरह की राय सामने आ रही है। एक वर्ग का मानना है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव जीतने को लेकर एक वर्ग आश्वस्त है, इसलिए वह वोट देने कम ही बाहर निकल रहा है। ऐसा कहने वालों में BJP समर्थक ज्यादा हैं। विरोधी वर्ग यह दावा कर रहा है कि उसके समर्थक बढ़-चढ़कर वोट डाल रहे हैं। लेकिन चुनाव विश्लेषकों की मानें तो हर वर्ग का मतदाता पिछले दो दौर के मतदान में निरुत्साहित नजर आया।

तीन तरह के वोटर | आज वोटरों की तीन श्रेणियां आसानी से निर्धारित की जा सकती हैं। पहली श्रेणी में वे प्रतिबद्ध मतदाता आते हैं, जो किसी भी एक दल से निष्ठा रखते हैं। दूसरी श्रेणी में वे वोटर हैं, जो आखिरी वक्त तक इस ऊहापोह में रहते हैं कि वोट दें या न दें। तीसरी श्रेणी के वोटरों को

वोट तो देना होता है, लेकिन किसे वोट देंगे यह फैसला आखिरी वक्त में मुद्दा और दल की नीति के आधार पर करते हैं।

जमीनी कार्यकर्ता | दूसरी और तीसरी श्रेणी के वोटरों को उत्साहित कर मतदान केंद्रों पर लाने का काम राजनीतिक दलों के जमीनी कार्यकर्ता करते हैं। जो मतदाता आखिरी वक्त तक अपना मन नहीं बना पाते उन्हें अपने दल की ओर मोड़ने में इन जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका खासी अहम होती है।

वैचारिक निष्ठा में कमी | हाल में जिस तरह राजनीतिक दलों और नेताओं की वैचारिक निष्ठा डांवाडोल हुई है और अपने विरोधियों को साथ लेने की कोशिशें बढ़ी हैं, उससे इन जमीनी कार्यकर्ताओं में निराशा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि ऐसे लोगों का वह समर्थन किस तरह करे। कई लोग कम मतदान के पीछे एक बड़ी वजह इन कार्यकर्ताओं के मन में उपजी निराशा को भी मानते हैं।

मौसम की भूमिका | वैसे, इस बार गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है। देश के कई इलाकों में हीटवेव चल रही है। बीते दो दौर के मतदान को देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा फिसड्डी रहे। दूसरी बात है कि इन दिनों दोनों राज्यों में शादियों का मौसम भी चल रहा है। बिहार की स्थिति यह है कि तकरीबन हर घर का एक या दो वोटर रोजी-रोटी के चक्कर में घर से दूर है। इसलिए चाहकर भी वोट देने नहीं लौट पा रहा।

प्रोत्साहन की जरूरत | वैसे, इसी माहौल में अभय कुमार जैसे चुनाव विश्लेषक भी हैं, जो कहते हैं कि भारत जैसे बहुरंगी और बहुसांस्कृतिक देश में औसतन दो से तीन प्रतिशत मतदान की कमी-बेसी असामान्य बात नहीं है। ऐसा पहले भी देखने में आता रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। इसके बावजूद राजनीतिक तंत्र और चुनाव आयोग को मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सोचना होगा।

लोकतंत्र की शर्त | राजनीतिक दलों के लिए यह सवाल अहम है कि मतदाता उदासीन क्यों हो रहा है? क्या उनके किसी व्यवहार और कर्म में बदलाव की जरूरत है? इसी तरह चुनाव आयोग को भी वोटरों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए नवाचार के बारे में सोचना होगा। उसे देखना होगा कि वह चुनाव प्रक्रिया में कैसा बदलाव लाकर जवाबदेह राजनीतिक तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र की सबसे अहम शर्त यह भरोसा ही है और इसी वजह से वोटर मतदान केंद्र की ओर खिंचा चला आता है। इस भरोसे को बनाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तो है ही, राजनीतिक तंत्र की सबसे ज्यादा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मोबाइल स्विच ऑफ करने से ऑन होंगी खुशियां

AI Image

जीवन आनंद

घर के लॉन में, सड़क पर, पार्क में, समुद्र के किनारे - बच्चा जहां भी जाता है वह उसके साथ होता है। बारिश में फिसलन भरी सीढ़ियों पर चढ़ने में उसे थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वह पीछा करना नहीं छोड़ता। यह विज्ञापन जिसने भी देखा है, जरूर याद होगा उसे। एक बच्चे और Pug की प्यारी-सी कहानी। पग डॉगी की एक नस्ल है और इस विज्ञापन ने उसे भारत में मशहूर कर दिया था, खासतौर पर बच्चों के बीच। यह एड था एक मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का, जो कहना चाहती थी कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा।

नया-नया जमाना था वह मोबाइल का। नए रिश्ते की तरह आम जीवन में आया मोबाइल अच्छा ही लगता था तब। लेकिन, अब रिश्ता पुराना हो चला है, पीछा भी लंबा हो चला है। हमेशा चिपक कर साथ-साथ चलने वाली यह आदत अब अच्छी नहीं लगती। थोड़ा स्पेस चाहिए, वक्त चाहिए। तो क्यों नहीं मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते?

जब वह एड आया तब नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन अब हमेशा की कनेक्टिविटी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कई लोगों के लिए। कोई समय नहीं होता, जब आप अकेले हों। आपने क्या देखा, क्या ऑर्डर किया, कहां गए और क्या खरीदा - इस कनेक्टिविटी की मेहरबानी से सब पर इंटरनेट की नजर है। ऐसे में कई बार खीझ होने लगती है, चिढ़ मचने लगती है मोबाइल की ट्रिंग-ट्रिंग और नोटिफिकेशन की पिंग-पिंग सुनकर। इस सिरदर्द से दूर होने और आनंद का नया रास्ता तलाशने का एक ही तरीका है, स्विच ऑफ।

यकीन जानिए, मोबाइल बंद करना खुशियों का रास्ता खोलना है। ऐसा लगेगा कि आप सारे सवालों से मुक्त हो चले हैं। कॉल, मेसेज, मेल का झंझट कुछ देर के लिए खत्म। इस समय जवाबदेही होगी तो सिर्फ खुद के लिए।

मोबाइल के चंगुल से छूटने के बाद पता चलता है कि हमारे पास कितना वक्त है जिस पर अभी तक इस डिवाइस ने कब्जा किया हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन से निकल कर अब लौट सकते हैं वास्तविक दुनिया में, जहां संवाद के लिए किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। जहां क्लिक, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब या अपलोडिंग के लिए कोई डेटा खर्च नहीं होता। यहां सब कुछ लाइव है और सारे काम बन जाते हैं एक मुस्कान से। कितने रिश्ते, कितनी मुलाकातें, खाने का स्वाद, किस्से-कहानियां - मोबाइल से छूटने के बाद पता चलेगा कि इसके चक्कर में आपसे क्या-क्या छूट गया था। यानी यही असली fear of missing out (FoMO) होना चाहिए, वह नहीं जो मोबाइल हमें बताता है। मोबाइल स्विच ऑफ कर आप मौका बना सकते हैं यह जानने का कि सबकुछ अब भी जज्बात और मेल-मिलाप से चलता है, अंगूठे के इशारे से नहीं।

टेक डिवाइस से कुछ अरसा दूर रहने को कहा जाता है digital detox। डीटॉक्स का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। मोबाइल जैसी टेक डिवाइस बहुत मददगार है हमारे लिए, लेकिन यह कुछ जहरीले तत्व भी दे रही है हमें। बेचैनी, नींद का गायब होना, रिश्तों में दूरी, तनाव - ये वो साइड इफेक्ट हैं, जो मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को मिलते हैं। इसकी नीली रोशनी में बहुत कुछ धुंधला हो जाता है। स्विच ऑफ का ऑप्शन चुनकर आप उस धुंध को साफ कर सकते हैं। याद दिला सकते हैं खुद को कि असली बॉस आप हैं और आपका जीवन किधर जाएगा, यह किसी ऐप के मैप से तय नहीं होगा। ध्यान रहे, खुशियां कभी नेटवर्क की मोहताज नहीं होतीं। यह तो भावनाओं पर चलती हैं।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'जीवन आनंद'

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो संबंध मजबूत नहीं बनेंगे

जे. कृष्णमूर्ति

हमारा जीवन खोखला है और हम प्रेम-शून्य होते जा रहे हैं। हम इंद्रियों की सनसनाहट को जानते हैं, दिखावे और प्रदर्शन को जानते हैं, यौनाचार की ललक को जानते हैं। पर इनमें कोई प्रेम नहीं रहता। फिर, कैसे इस खोखलेपन में बदलाव लाया जाए, कोई कैसे उस लौ को पाएं जिसमें धुआं न हो? मुद्दे के सच को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं।

हम बड़े सक्रिय रहते हैं, किताबें लिखने में लगे रहते हैं, सिनेमा जाते हैं, खेलते हैं, प्रेम करते हैं, काम पर जाते हैं, फिर भी हमारा जीवन खाली-खाली-सा, उबाऊ और एक नीरस दिनचर्या बन कर रह गया है। हमारे संबंध इतने दिखावटी, खोखले और इतने बेमानी क्यों हो गए हैं? हम अपने जीवन को इतना तो जानते ही हैं कि हमारे वजूद के कोई खास मायने नहीं हैं। हम उन सूत्रों, सूक्तियों और विचारों को दोहराने में लगे रहते हैं जो हमें रटा दी गई हैं- महात्माओं की तरफ से, संतों से और हम किसी न किसी के पीछे ही चलते रहते हैं, वह चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर बौद्धिक। हम केवल ग्रामोफोन रिकार्ड जैसे हो गए हैं- जो भर दिए गए को दोहराता चला जाता है, और इसी को हम 'ज्ञान' कह देते हैं। उसी को बार-बार गाते रहते हैं, पर हमारा जीवन फिर भी उबाऊ और बेरंग बना रहता है।

कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम भावुक हो जाएं, भावना में बहने लगें। हम इस खोखलेपन को जानते हैं, खिन्नता के इस विचित्र एहसास से वाकिफ हैं। हमारे जीवन में इतनी नकारात्मकता आखिर क्यों है? निश्चित रूप से इसे हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम अपने रिश्तों में सजग रहकर, उनसे अवगत रह कर इसे देखेंगे। क्या हमारे संबंध बस अपने ही बारे में सोचते रहने तक ही सीमित नहीं हैं? क्या मन की हर गतिविधि खुद को बचाने, अपनी सुरक्षा चाहने और खुद को दूसरों से अलग समझने की प्रक्रिया भर नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि हमारी सोच बस खुद को अलग समझने की प्रक्रिया बनी रहती है। भले ही हम उसे सब के लिए सोचने का नाम दे देते हों, अपने जीवन में हम जो कुछ करते हैं, क्या वह खुद को अपने ही खोल में बंद किए रहने की प्रक्रिया नहीं है?

अपने जीवन में आप यह स्वयं देख सकते हैं। परिवार अपने आपको खुद में समेट लेने की और अलग कर लेने की प्रक्रिया बन कर रह गया है। हर गतिविधि हमें अलगाव की ओर ले जाने वाली हो गई है। और इसी से खोखलेपन और खालीपन का एहसास पनपने लगता है। खाली होने के कारण ही तो हम इसे भरने की कोशिश करने लगते हैं रेडियो से, शोर-गुल से, गप्पें मारने से, पढ़कर ज्ञान अर्जित करने से, नाम या पैसा कमाने से, और सामाजिक हस्ती बन जाने जैसी अनेक बातों से। पर अपने आप को खुद में समेटने वाले काम ही तो हैं और इसलिए ये हमारे अलगाव को और बढ़ा देते हैं। तभी तो अधिकांश लोगों के लिए जीवन अलगाव की, नकारने की, प्रतिरोध की और किसी ढर्रे पर चलने की प्रक्रिया बन कर रह गया है। और निश्चित ही इस प्रक्रिया में जीवन दरअसल जीवन नहीं रह जाता है।

(साभार : पुस्तक 'प्रेम क्या है?')

कोई देश अमीर तो कोई गरीब क्यों

मृत्युंजय राय

कोई मुल्क अमीर क्यों होता है और कोई दूसरा गरीब क्यों रह जाता है? यह बहस पुरानी है। Jared Diamond ने **'Guns, Germs and Steel'** नाम की किताब में बताया कि यूरोपीय देश विकास की दौड़ में क्यों आगे निकल गए। नब्बे के दशक के आखिर में अमेरिकी लेखक ने यह किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों यूरेशिया (यूरोप और एशिया) और उत्तरी अफ्रीका की सभ्यताएं बच गईं और किन वजहों से उन्होंने दूसरों को अपने अधीन बनाया। जेरेड डायमंड ने लिखा कि यूरेशियाई देशों के दबदबे की वजह टेक्नॉलजी की वजह से थी।

AI Image

विचार विंडो

आज फिर दुनिया बड़े तकनीकी बदलाव से गुजर रही है। जेनरेटिव AI के जिस तरह से रोजगार पर असर डालने की आशंका है, उसकी वजह से एक बार फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर चर्चा शुरू हो गई है। खैर, जेरेड डायमंड ने जो विषय उठाया था, उसी पर David Landes's की किताब **The Wealth and Poverty of Nations** है। इसमें लेखक ने बताया है कि दुनिया में क्यों कुछ देशों की इकॉनमी तरक्की करती गई और क्यों दूसरे देशों के हाथ वैसी कामयाबी नहीं लगी।

डेविड का मानना है कि किसी देश की तरक्की के लिए अगर कोई एक बात अहमियत रखती है तो यह कि वहां कितना खुलापन है। वह लिखते हैं कि तरक्की के लिए किसी देश को दूसरी जगहों से बेहतरीन प्रैक्टिस को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसके ऐसा करने से वहां के अभिजात वर्ग को नुकसान पहुंचे। डेविड बताते हैं कि कम बजट घाटा, व्यापार में कम से कम अवरोध और प्रतिस्पर्धी एक्सचेंज रेट जैसी अच्छी आर्थिक नीतियां किसी देश की तरक्की के लिए अहम तो हैं, लेकिन काफी नहीं। वह लिखते हैं कि कामयाबी और नाकामी में सिर्फ तकनीक तक पहुंच और नए आइडियाज का ही अंतर नहीं होता। कामयाबी इस पर भी निर्भर करती है कि तकनीक और नए आइडिया का कोई देश कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। डेविड बताते हैं कि तरक्की के लिए इनोवेशन पर लगातार काम होते रहना चाहिए। किसी देश की तरक्की सिर्फ बड़े इनोवेशन पर ही आश्रित नहीं होती। सबक यही है कि लगातार कोशिश की जाए।

अफसोस की बात यह है कि आर्थिक नीतियों में खुलेपन के जिस रास्ते की डेविड ने वकालत की है, आज दुनिया उससे उलटे रास्ते पर चल रही है। आज संरक्षणवाद बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉनल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा दे चुके हैं। अगर वह फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका दोबारा व्यापार युद्ध शुरू कर सकता है।

लेकिन अब तक का तजुर्बा यही बताता है कि आर्थिक खुलापन समृद्धि लेकर आता है। खुद, भारत ने जब नब्बे के दशक में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता चुना तो उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। भारत 'हिंदू ग्रोथ रेट' के दौर से निकलकर आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेज इकॉनमी बन चुका है।

यही नहीं, 2027 तक उसके तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका और चीन के बाद भारत का आर्थिक परचम सबसे ऊंचा लहरा रहा होगा। भारत और चीन को ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ है। दोनों ही देश आर्थिक उदारीकरण के पैरोकार हैं। अफसोस की बात यह है कि पहले जहां अमीर देश आर्थिक खुलेपन की वकालत करते थे, अब वहीं से इसके विरोध की आवाजें उठ रही हैं।

रिश्ता टिके कैसे

प्रणव प्रियदर्शी

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प मामले का निपटारा किया, जिसमें पति और पत्नी दोनों चाहते थे कि उनकी शादी निरस्त कर दी जाए। आधार यह था कि शादी में प्रमुख रस्में पूरी नहीं की गई थीं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कपल की इच्छा पूरी की, लेकिन साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर लेक्चर भी दिया। कहा गया कि अगर उपयुक्त रीतियों का पालन न हो तो उस शादी को संपन्न हुआ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी सिर्फ 'नाच-गाना' और 'खाना-पीना' नहीं होता।सवाल यह है कि ऐसा हो भी तो दिक्कत क्या है? इस देश में सैकड़ों तरह से शादियां की जाती हैं। कोर्ट-कचहरी या सरकार-पुलिस को इस सवाल में एक हद से ज्यादा घुसने की जरूरत क्या है कि ये शादियां किन तरीकों से हो रही हैं। जिस किसी तरीके से हो, वे इसे दर्ज कर लें, इतना ही काफी है। शादी की असली कसौटी है तलाक। शादी को मजबूत और टिकाऊ बनाने की चिंता में घुलते हुए हम न केवल उसकी पवित्रता के नए-नए तराने गढ़ते रहते हैं बल्कि तलाक को अधिक से अधिक कठिन बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। आखिरकार ये सारे जतन हमें एक समाज के रूप में कट्टर, संकीर्ण और अतीतजीवी बनाते हैं। विवाह की कथित पवित्रता का सारा बोझ महिलाओं के सिर पर पड़ता है। न केवल एक पत्नी के रूप में उन्हें पूरे परिवार की ज्यादतियां सहन करते चलने का दायित्व शिरोधार्य करना पड़ता है बल्कि बेटी, बहन वगैरह की भूमिका में भी अपनी इच्छाओं को परिवार की कथित इज्जत और मान मर्यादा के घेरे मैं कैद करना पड़ता है। इस सबसे बचने का आसान उपाय यह है कि विवाह से जुड़ी पवित्रता के तमाम मिथकों का मोह कम किया जाए और तलाक को अधिक से अधिक आसान बनाया जाए। रिश्ता टिके, लेकिन आपसी प्यार, स्नेह और विश्वास की बदौलत, ना कि तलाक की तकलीफदेह प्रक्रिया और समाज में होने वाली बदनामी के डर से।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ उड़ जाती हैं मुश्किलें

जीवन आनंद कॉलम में 29 अप्रैल को प्रकाशित लेख 'हवा के साथ आवारा सफर का मजा लीजिए' पढ़ा। इस कॉलम में जीवन की गंभीर बातों को बड़ी सरलता के साथ पेश किया जाता है। लेखक ने बिलकुल सही कहा है कि हवा के साथ का सफर अनूठा महसूस होता है। हवा की लहरों के बीच दिमाग बहुत जल्द तरो-ताजा हो जाता है और मन भी कुलांचे भरने लगता है। शरीर और मन की तमाम ऊर्जा को इकट्ठा करना आसान हो जाता है जिससे अपनी ही क्षमता बढ़ी हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है, तेज हवा अपने साथ जीवन की सारी मुश्किलों को उड़ाकर ले जा रही हों।

शालू रानी गुप्ता, विकासपुरी

■ हवा से गहरा नाता

यह पत्र 'हवा के साथ आवारा सफर का मजा लीजिए' लेख से संबंधित है। हवा के विरुद्ध चलना एक अनोखा और मिश्रित अनुभव है। यह चुनौती और ताजगी दोनों का एहसास कराता है। तेज हवा में चलने से आपके शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। हवा के विरुद्ध चलना प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है और उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है।

रोहित कुमार, ईमेल से

■ जीवन और प्रकृति

अपने लगाए पेड़ में पहली बार फूल खिलते देखना एक अद्भुत और अतुलनीय अनुभव है। यह आनंद सिर्फ खूबसूरती देखने का नहीं होता, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा होता है। आपने एक छोटे से बीज या पौधे को बड़ा होते देखा है, उसकी देखभाल की है और अब वह आपके प्रयासों का फल दे रहा है। यह आत्मविश्वास और प्रकृति से जुड़ाव का बेहतर उदाहरण है। प्रियजनों के साथ इस खुशी को साझा करने से आनंद और भी बढ़ जाता है।

कृतिका झा, ईमेल से

जीवन आनंद

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

तापमान फिर 40 पार, अभी और बढ़ेगी गर्मी – एक खबर – यह तो केवल झांकी है, असली खेल अभी बाकी है!

सुशील गुप्ता

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

फिलिस्तीन का समर्थन

विश्वविद्यालयों में आंदोलन

फिलिस्तीन-समर्थक विरोध प्रदर्शन करने वालों ने दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में आंदोलन छेड़ दिए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस व अन्य देशों में ज्यादा से ज्यादा छात्र इज़राइल-विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। इससे शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक विचारधाराओं और विश्व दृष्टिकोण बदलने में उनकी भूमिका के बारे में बहस छिड़ गई है। सवाल है कि छात्रों को राजनीति में शामिल होना चाहिए या नहीं। परिसरों में इज़राइल-विरोधी परिघटना को अलग-थलग कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह वयापक भू-राजनीतिक सोच तथा सामाजिक आंदोलनों को अभिव्यक्ति देती है। लेकिन ऐसे विरोध प्रदर्शनों के लिए खासकर शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने से विश्वविद्यालयों के उद्देश्य तथा 'कट्टरता' फैलाने के मुकाबले बेहतर रचनात्मक संवाद विकसित करने की जिम्मेदारी पर भी महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। इस घटनाक्रम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समावेशन व विविधता को प्रोत्साहन के बीच टकराव पैदा हो गया है। यदि इज़राइल-विरोधी प्रदर्शन सम्मानपूर्ण ढंग से न हों तथा ये संवाद के बजाय टकराव पर केन्द्रित हो जाएं तो इनसे छात्रों के एक तबके का हाशियाकरण होगा। इज़राइल-समर्थक प्रदर्शन भी सबसे पहले अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में दिखे थे। इज़राइल द्वारा आत्मरक्षा में गाजा पर हमले के बाद इन विश्वविद्यालयों में एक समानान्तर अभियान छेड़ा गया। वास्तव में अमेरिका और यूरोप में इज़राइल-समर्थक भावनायें भी बहुत बढ़ गई हैं। इसका कारण यह है कि इज़राइल की तरह उन्होंने अपने खिलाफ भी आतंकी, कट्टरपंथी व जिहादी हमले देखे हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संभवत: नवीनतम इज़राइल-विरोधी प्रदर्शनों के पीछे भी ऐसे तत्व शामिल हैं। इज़राइली भी अपने देश के खिलाफ जिहादी भावना से किए जाने वाले हमलों के खिलाफ मजबूती से नेतनयाहू के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं।

संस्कृत में कहावत है, 'या विद्या स विमुक्तये', अर्थात शिक्षा मुक्तिदाता है। यह सार्वभौम तथ्य है, इसलिए मुक्ति सबसे पहले छात्रों के व्यवहार से दिखनी चाहिए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विरोध की कोई सीमायें नहीं होती हैं और ऐसे प्रदर्शनों में हिंसा की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। छात्रों को कालेज परिसरों में अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनसे इसकी ही उम्मीद की जाती है। लेकिन यदि वे अपने आसपास की घटनाओं से अनभिज्ञ हों तो यह भी शिक्षा के लिए अनुचित होगा। इसी प्रकार उनसे अपने आसपास होने वाली गड़बड़ियों पर प्रतिक्रिया की भी उम्मीद की जाती है। यह भी समान रूप से सच है कि वे अपने आसपास के सामाजिक बदलाव से अप्रभावित नहीं रह सकते हैं। अपने देश में हमें नहीं भूलना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने आपातकाल का विरोध किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अनेक नेताओं ने कालेज छोड़ दिए थे और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। भगत सिंह ने छात्रों के राजनीति में शामिल होने के सवाल पर लिखा था, 'क्या इंग्लैंड और जर्मनी के छात्रों द्वारा कालेज छोड़ कर युद्ध में शामिल होना राजनीति नहीं है? ऐसे में उपदेशक कहां थे? उन्होंने छात्रों से पढ़ने को क्यों नहीं कहा? केवल छात्रों और नौजवानों के प्रयासों से ही आज अनेक देश स्वतंत्र हुए हैं।' हालांकि, यह तथ्य भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि इज़राइल हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहा है और हमास आतंकियों द्वारा उस पर हवा, धरती व समुद्र से किया हमला द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हुए 'यहूदी नरसंहार' के बाद सबसे बड़ा था।

भू-राजनीति पर आतंकवाद का प्रभाव

भू-राजनीतिक उथलपुथल तथा क्षेत्रीय टकरावों के इस युग में आतंक का खतरा बढ़ रहा है। यह सीमाओं को पार कर पूरे दुनिया के स्थायित्व को खतरे में डाल रहा है।

सुधीर हिंदवान
(लेखक, रणनीति विशेषज्ञ हैं)

आज दुनिया की राजनीति अनेक क्षेत्रीय टकरावों का सामना कर रही है। इसमें इज़राइल-फिलिस्तीन व रूस-यूक्रेन युद्ध तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान में उथलपुथल के साथ वैश्विक आतंकवाद पिछले कुछ सालों में सुर्खियों में आया है। इसी प्रकार घरेलू स्तर पर सीमापार के आतंकी संगठनों ने कश्मीर में आतंक छेड़ रखा है तथा वे हत्यारों के गिरते मनोबल को थामने के लिए मीडिया में सुर्खियां जुटा रहे हैं। इसी के साथ ही दुनिया भर में आतंकी षडयंत्र सामने आए हैं जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाल सागर, इज़राइल, फिलिस्तीन, स्कैंडनेवियाई देश, मध्य एशिया व रूस शामिल हैं।

पिछले कुछ दिनों में विद्रोहियों ने अनेक निरपराध लोगों की जान ली है तथा जम्मू कश्मीर व भारत के अन्य घरेलू मोर्चों पर अनेक सैनिकों ने शहादत दी है। हालांकि, घरेलू आतंक की तुलना में अंतरराष्ट्रीय आतंक में तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमी आई है, पर सरकारों के लगातार मुकाबले के प्रयासों के बावजूद इसने सारी सीमायें पार की हैं। अमेरिका में वर्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन पर आतंकी हमलों के बाद काफी खून बहा है और इसके बाद विश्व स्तर पर आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले वर्षों में बार-बार होने वाले आतंकी हमलों में कभी थोड़ी कमी आई, पर इनसे सुरक्षा और खुफिया नेटवर्कों की कमियां भी उजागर हुई हैं। इसके साथ ही इस विभीषिका से निपटने में आधुनिक राष्ट्रों का विश्वास भी प्रभावित हुआ है। आतंकवाद चाहे क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, यह लंबे समय तक बिना अंतरराष्ट्रीय समर्थन या सहयोग के जीवित नहीं रह सकता है। वैश्वीकृत दुनिया में सत्ता के खेल स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का असमान ढांचा दुनिया के विभिन्न भागों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और परस्पर संबंधों में ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। शीतयुद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था अब भी सत्ता का खेल बनी हुई है। हिंसा और आतंक पर अनेक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय है कि पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में वर्चस्ववादी नेटवर्क लगभग सभी राष्ट्रों में विपक्षी शक्तियों का सामना कर रहे हैं।

इस प्रकार समाजों का वैश्वीकरण हुआ है, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपारदर्शिता बढ़ी है जिसके कारण गरीब देशों में लोग अपनी खराब सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए बड़ी शक्तियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शीतयुद्ध ने अफगानिस्तान, दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी और लैटिन अमेरिकन देशों में हस्तक्षेप किया था जिसके परिणामस्वरूप खास किस्म के परिवर्तन हो रहे हैं तथा आंतकी गतिविधियां फलने-फूलने का मैदान साफ हो रहा है। यदि शक्तिशाली देश शुरुआत से ही ठीक काम करते तो अफगानिस्तान के तालिबानीकरण की नौबत न आती। शुरुआत में आतंकवाद की सामाजिक बीमारी की पहचान में विफलता के कारण अनेक देश संकट में फंस गए हैं।

तथाकथित दुष्ट देशों पर हथियार और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में नकारात्मक नतीजे निकले हैं और इन देशों को अंतरराष्ट्रीय हमदर्दी मिलने में आसानी हुई है। हालांकि, आतंकवादी समस्या के स्थाई समाधान की उम्मीद अभी बहुत दूर है, पर उम्मीद है कि शक्तिशाली देश आतंकवाद के प्रति बेहतर समझदारी विकसित करेंगे जो खतरनाक आयाम धारण करती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन में तेजी आने तथा एके47 जैसे संवेदनशील हथियारों व प्लास्टिक विस्फोटकों-आरडीएक्स के प्रचार ने दुनिया भर में आतंकवादी नेटवर्कों के विस्तार में मदद की है। इसके साथ ही आतंकियों के नए आत्मघाती दस्तों ने राज्यों के पूरे सुरक्षा नेटवर्कों को गंभीर खतरे में डाल दिया है। हालिया घटनाओं को अलग-थलग कर नहीं देखा जा सकता है।

एक प्रमुख आतंकवाद-विरोधी विशेषज्ञ ब्रायन जेन्किन्स का विश्वास है कि पुलिस व खुफिया विकभाग के बीच बेहतर समन्वय तथा प्रयास तेज करने से संभावित आतंकी हमलों की जानकारी मिल सकती है, पर अभी भी इस बात पर भ्रम है कि क्या ऐसी व्यवस्था कट्टरपंथ से संचालित आतंकियों से निपटने में सक्षम होगी। धीरे-धीरे धर्म विश्व स्तर पर आतंकवाद की मुख्य प्रेरक शक्ति बनता जा रहा है। आतंकवादियों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधी नेटवर्कों के बीच गठजोड़ मजबूत हो रहा है। संगठित अपराध और राजनीतिक हिंसा पर ब्रिटिश विश्लेषक एलीसन जैमीसन का कहना है कि हाल में आतंकवाद तथा संगठित अपराध के बीच विभाजक रेखायें बहुत धुंधली हो गई हैं।

इटली में संगठित अपराध विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नेस्टो ने कहा था, 'आतंकी का लक्ष्य वैचारिक होता है, जबकि संगठित अपराधी का वित्तीय, लेकिन दोनों का उपकरण एक है। इन दोनों को पैसे और हथियारों की जरूरत होती है।' श्रीलंका में तमिल टाइगर्स अपने संघर्ष के लिए पैसा जुटाने हेतु नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं तथा पूर्वोत्तर भारत में गुरिल्ली चाय बागान मालिकों का अपहरण कर उनसे पैसा वसूलते हैं ताकि अलगावाद के लिए संघर्ष चलाया जा सके। चेचेन्या में अलगाववादी नशे के व्यापार में अत्यधिक संलिप्त हैं। इन दिनों आतंकवादी जोखिम वाले बिंदुओं तक पहुंचने में पहले की तुलना में ज्यादा विश्वास से भरे हैं। वे हमले करने के पहले उनकी योजना बनाते हैं तथा नायक के रूप में उनको उचित ठहराते हैं। इस प्रकार वे अपने कृत्यों के माध्यम से अनेक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भय पैदा करते हैं तथा कुछ लोगों को प्रेरित भी करते हैं। इसलिए प्रभावी प्रशासनिक उपायों के लिए हमें पहले आतंकवादियों के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना चाहिए। सरकारी स्तर पर सचमुच प्रभावी तैयारी कार्यक्रम जरूरी हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आतंकी गतिविधियों में कौन लोग शामिल हैं और उनकी प्रेरणा क्या है। आतंकी घटना से निपटने तथा उसके प्रभावों को समाप्त करने के लिए सतर्कता से योजना बनानी होगी। आतंकी-प्रभावित क्षेत्र के बारे में समुचित डेटा से बहुत सहायता मिलती है। खुफिया तंत्र को आतंकी लक्ष्यों, समय और स्थलों के बारे में पहले से ही सूचनायें उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन अकेले सरकार ही आतंकवादी घटनायें रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है। सुरक्षा की सामान्य स्थितियों में सुधार के लिए लोगों और व्यक्तियों को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा। इसके साथ ही ऐसी संवेदनशील सुरक्षा प्रक्रियाओं की जरूरत है जो हवाईअड्डों पर स्क्रीनिंग के साथ ही सीमा क्षेत्रों में स्क्रीनिंग तक प्रभावी हों।

एक प्रकार के सकारात्मक कार्यक्रमों की भी जरूरत है जो आतंकियों में निराशा का स्तर बढ़ सकें। ऐसे कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक संस्थानों समेत ऐसे संस्थान खोलने की जरूरत है जो नस्ली, धार्मिक व राजनीतिक दबावों को सहन कर आतंकियों को अपनी भावनायें समुचित तरीके से व्यक्त करने का अवसर दे सकें। इससे उनको अपनी सोच बदलने तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेद दूर करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान युग में आतंकी एक दशक पहले के अपने समकक्षों की तुलना में बहुत संगठित तथा ज्यादा पेशेवर होते हैं, इसलिए सुरक्षा और संरक्षा की नई अवधारणायें विकसित करने की जरूरत है। इसके साथ ही सतर्क व अत्यधिक प्रभावी पुलिस व अर्धसैनिक नेटवर्क बनाना भी जरूरी है।

आशंका है कि जैविक व रासायनिक हथियारों की उपलब्धता के साथ ही आतंकी अपना अभियान और जोश के साथ चलाएंगे। कोई भी सभ्य राजनीतिक व्यवस्था उस समय तक प्रगति नहीं कर सकती है, जब तक आतंकवाद का उस समय तक उन्मूलन न कर दिया जाए जब तक इसका राजनीतिक समाधान सामने न आए। समय की आवश्यकता है कि आतंकवाद पैदा करने वाली समस्याओं के समाधान हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित की जाए। आतंकवाद से प्रभावित राज्यों को विवादों के बातचीत से समाधान के रास्ते खोलने चाहिए। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति भी प्रदर्शित करनी चाहिए।

डिजिटल जगत की सुरक्षा

डिजिटल परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, साइबर खतरे अधिक परिष्कृत और व्यापक होते जा रहे हैं।

शायनी शर्मा
(लेखिका, शिक्षा प्रदाता हैं)

कनेक्टेड डिवाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग और विभिन्न अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रसार के साथ, व्यक्तिगत हैकर्स से लेकर संगठित साइबर आपराधिक समूहों तक के खतरों की आक्रमण सतह में काफी विस्तार हुआ है। इस युग में, जहां प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, साइबर सुरक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है और प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, इसे नए खतरों का उद्भव माना गया है।

साइबर सुरक्षा उपाय, जैसे एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण और डेटा हानि की रोकथाम, अनधिकृत पहुंच, चोरी और गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने में मदद करते हैं। व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी के युग में, गोपनीयता बनाए रखना, व्यक्तिगत जानकारी और संचार को अनधिकृत निगरानी से सुरक्षित रखना, चोरी और आक्रामक डेटा संग्रह प्रथाओं की पहचान करना न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि संगठनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आदर्श वाक्य यह है कि हमारी डिजिटल दुनिया की रक्षा करना एक जिम्मेदारी है जिसे हम सभी साझा करते हैं।

साइबर सुरक्षा शोधकर्ता विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, चाहे वह साइबर विरोधियों की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं (टीटीपी) को समझना हो या सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र में सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए कार्यप्रणाली, उपकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना हो; इसका उद्देश्य डिजिटल संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान करना है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता उनके मूल कारणों को समझने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कमजोरियों की जांच करते हैं।

चाहे व्यवसाय हो या शिक्षा, कार्य के सभी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा की सुरक्षा करना अनिवार्य है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों का अभिन्न अंग है, क्योंकि साइबर खतरे भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को आकार देने में संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत सरकार ने विभिन्न पहल और नीतियां लागू की हैं जैसे साइबर सुरक्षित बारात; भारत में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र और कई अन्य। इन पहलों का उद्देश्य नवीनतम साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उपकरणों से दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाना और हटाना और अंतत: एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर साइबर खतरों से निपटना है।

डिजिटल परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, साइबर खतरे अधिक परिष्कृत और व्यापक होते जा रहे हैं। खतरे का पता लगाने, घटना की प्रतिक्रिया और भेद्यता प्रबंधन सहित साइबर सुरक्षा उपाय मैलवेयर, फ़िशिंग, रैंसमवेयर और सेवा से इनकार करने वाले हमलों जैसे साइबर खतरों को पहचानने, कम करने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

प्रभावी साइबर सुरक्षा ग्राहकों, भागीदारों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर जनता सहित हितधारकों के बीच विश्वास और विश्वास पैदा करेगी। साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं और नियमों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके, संगठन डिजिटल बाज़ार में अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।

उभरते खतरे के परिदृश्य, तकनीकी प्रगति, डिजिटल परिवर्तन पहल, नियामक आवश्यकताओं, भू-राजनीतिक तनाव और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर सामाजिक निर्भरता के कारण साइबर सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ गई है। साइबर सुरक्षा केवल डेटा की सुरक्षा के बारे में नहीं है बल्कि यह डिजिटल युग में विश्वास, गोपनीयता और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में है। साइबर खतरों से उत्पन्न उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी, नीतियों, शिक्षा, सहयोग और निवेश को शामिल करते हुए एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

ऑनलाइन स्थान को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को सतर्क, सूचित और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। मजबूत पासवर्ड, नियमित अपडेट और फ़िशिंग प्रयासों से सावधान रहना साइबर लचीले समुदाय की ओर बस कुछ ही कदम हैं। प्रगति के बावजूद, साइबर सुरक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें साइबर खतरों का निरंतर विकास, कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी और साइबर अपराध की वैश्विक प्रकृति शामिल है।

आप की बात

रायबरेली से राहुल

रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन से की नयी रणभूमि ष् सम्बंधित है। इससे हफ्तों का सस्पेंस समाप्त हुआ लेकिन अमेठी के बजाय रायबरेली को चुन कर राहुल गाँधी ने अपने दृष्टिकोण से अच्छा कदम उठाया है। उनके लिए तुलनात्मक दृष्टि से रायबरेली काफी आसान सीट है, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी उनको कड़ी टक्कर दे सकती थीं। अगर गाँधी परिवार से कोई भी सदस्य अमेठी या रायबरेली से नहीं लड़ता तो एक गलत राजनैतिक सन्देश जाता और इसके अतिरिक्त कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कार्यकर्ताओं में निराशा की लहर दौड़ जाती। 25 वर्षों में पहली बार अमेठी से गाँधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। भाजपा राहुल गांधी के वायनाड के बाद अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को पलायन बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक उड़ाते हुए-डरो मत, भागो मत कहा है। हालांकि, चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल सवाल है कि क्या राहुल गांधी मतदान के बाद वायनाड में हार की आशंका से रायबरेली आए हैं अथवा उनका इरादा हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस में जान डालना है। देखना होगा कि क्या इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आबंटित 17 सीटों पर उसके प्रदर्शन में कुछ सुधार आएगा और राहुल-अखिलेश संयुक्त चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं।

- बाल गोविंद, नोएडा

कांग्रेस में घबराहट

पिछले काफी समय से कांग्रेसी दलबदल कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सामान्य से लेकर विशिष्ट नेता तक संसद में अपनी जगह बनाने के लिए स्थान तक बदल रहे हैं। जन-आशीर्वाद से हमेशा लोकसभा पहुंचने वाली सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंची। राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा पहुँचते रहे, पर पिछले चुनाव में वे वायनाड से लोकसभा सदस्य बने और इस बार तो उन्होंने गजब कर दिया। वायनाड के साथ ही वे अमेठी से भी नामांकन भरने वाले थे। लेकिन अचानक मन बदल कर माताजी और बहनजी के साथ दादी इंदिरा गांधी की विरासती सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। आखिर कांग्रेस पार्टी में घबराहट क्यों बढ़ती जा रही है? कांग्रेस बरसों सत्तासीन रही है और ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक उसका एकछत्र शासन भी रहा है। तब पिछले दस साल में ही इतनी घबराहट क्यों पैदा हो गई है? भाजपा भी तो बरसों सत्ता से बाहर रही, पर उसमें इतनी घबराहट व बेचैनी कभी पैदा नहीं हुई। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार जनसंघ व भाजपा के पास कांग्रेस को सत्ता से हटाने का कोई शार्टकट नहीं था, उसी तरह मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भी सत्ता से हटाने का कोई शार्टकट नहीं है।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

ऋषि सुनक का भविष्य

देखना है कि ऋषि सुनक का बोझ कन्जरवेटिव पार्टी कितने दिनों तक उठा सकती है? हो सकता है इस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आगामी आम चुनाव तक सुनक को ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बनाए रखे ताकि पार्टी की संभावित ऐतिहासिक पराजय का ठीकरा भी उनके माथे पर फोड़ा जा सके। कन्जरवेटिव पार्टी ने ब्रेक्सिट का जो फायदा बताया था उसका ठीक उल्टा हो रहा है। दो महीने में तीन प्रधानमंत्री आए, लेकिन सुनक अभी पद पर बने हुए हैं। लेकिन स्थानीय चुनाव के नतीजे ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। कंजरवेटिवों को पिछले कुछ वर्षों में सबसे खराब स्थानीय चुनाव परिणामों का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी शुरू से ही ब्रिटेन के यूरोपीय संघ-ईयू से अलग होने का विरोध करती रही है। चुनाव में विजय के बाद वह फिर ब्रिटेन को ईयू में शामिल कर सकती है। हालांकि, यह प्रक्रिया बहुत आसान नहीं होगी और काफी कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम, अमेरिका-ईयू संबंधों तथा उस समय वैश्विक स्थितियों पर निर्भर करेगा। ऋषि सुनक के भविष्य से उन लोगों की भावनायें भी प्रभावित होंगी जो भारतीय मूल के व्यक्ति के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और इसे असाधारण प्रगति मानते थे।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

आत्मविश्वास की भावना

कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। लंबे समय से यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। इसके बावजूद वर्तमान माहौल में यहां राहुल को कड़ी टक्कर का सामना करना होगा। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा में जाने के करण अब कांग्रेस यहां से एकतरफा जीत की उम्मीद नहीं कर सकती है। यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी वायनाड से भी क्यों चुनाव लड़ते? आत्मविश्वास की भावना नरेन्द्र मोदी में कूट-कूट कर भरी है जो प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद मोदी जी केवल बनारस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है कि उनको उन्हें यहां से पिछली बार से भी अधिक वोटों से जीत का पूरा विश्वास है। नेताओं में आत्मविश्वास की भावना का खामियाजा देश की जनता तथा सरकारी खजाने को भुगतने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पहले कोई उम्मीदवार कई सीटों से चुनाव लड़ सकता था, पर बाद में इसे केवल दो सीटों तक सीमित किया गया। समय आ गया है कि अब निर्वाचन आयोग किसी भी उम्मीदवार के केवल एक सीट से लड़ने का प्राविधान करे। इससे नेता ज्यादा गंभीर बनेंगे।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

गहरी नींद और खुला संवाद स्वास्थ्य के आधार हैं

फिर सिर उठाते आतंकी

इसमें संदेह नहीं कि पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले का एक मकसद अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होगा। इस हमले में एक जवान बलिदान हुआ और पांच घायल हो गए। आतंकियों की तलाश में सघन अभियान जारी है, लेकिन न केवल यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें खोजकर ठिकाने लगाया जाए, बल्कि यह भी कि इस तरह के हमलों की उनकी क्षमता का दमन किया जाए। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चुनावों के चलते पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में भी आतंकी इसी तरह के हमले करने की वैसी ही कोशिश कर सकते हैं, जैसी उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों के ठीक पहले पुलवामा में की थी। इस आशंका का एक बड़ा कारण राजौरी-पुंछ क्षेत्र की पीर-पंजाल पर्वतमाला में आतंकियों की सक्रियता है। इस इलाके में पिछले एक वर्ष में सेना के काफिलों पर कई आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में लगभग 20 सैन्य अफसरों और जवानों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है। यह एक बड़ी क्षति है। पुंछ-राजौरी इलाके में आतंकी हमलों का सिलसिला तभी बंद होगा, जब पीर-पंजाल की पहाड़ियों में ठिकाना बनाने वाले आतंकियों और उनकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों पर सख्ती की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि सीमा पार से आतंकी पीर-पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों में छिपने और फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर सुरक्षित बच निकलने में सफल न होने पाएं। यह ठीक नहीं कि वे बचकर निकल जाते हैं।

वास्तव में पीर-पंजाल की पहाड़ियों और गुफाओं में एक बार फिर आपरेशन सर्प विनाश जैसे किसी सैन्य अभियान की आवश्यकता है। करीब दो दशक पहले छेड़े गए इस अभियान में बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया गया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से आए अथवा उसकी शह पर सक्रिय आतंकियों ने पीर-पंजाल में फिर से अपना ठिकाना बना लिया है। आशंका इसकी भी है कि कुछ स्थानीय लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं। यह ध्यान रहे कि वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी एक बस्ती से निकल कर आए थे। यह हमला यह भी बताता है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने और उनकी सहायता करने से बाज नहीं आ रहा है। यह मानने के भी अच्छे-भले कारण हैं कि आतंकी कश्मीर के स्थान पर जम्मू क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसके कारणों का पता लगाकर उनका निवारण करने का समय आ गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर दबाव बनाने के भी नए उपाय खोजे जाने चाहिए, क्योंकि वह रणनीति बदल-बदलकर जम्मू-कश्मीर में हस्तक्षेप करता ही रहता है। भारत सरकार को उन तत्वों के खिलाफ भी अपनी निगाह टेढ़ी करनी होगी, जो आतंकी गतिविधि बढ़ते ही पाकिस्तानपरस्ती का परिचय देने लगते हैं।

जल उत्सव

उत्तराखंड यूं तो सदानीरा गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, लेकिन यह भी सच है कि जल संरक्षण की आवश्यकता यहां भी पड़ती है। राज्य को सूखते जल स्रोत, सूखती नदियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में प्रति वर्ष औसतन 1529 मिमी वर्षा होती है और इसमें अकेले मानसून का योगदान 1176 मिमी से अधिक है। इस वर्षा जल का अधिकांश हिस्सा यूं ही व्यर्थ चला जाता है। अगर इस जल का कुछ हिस्सा सहेज लिया जाए तो राज्य में लगातार गहराते जल संकट का काफी हद तक समाधान हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में प्रयास अब तक न किए गए हों। कैच द रेन, हरेला, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से विभिन्न विभागों ने वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इसके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाए। यही नहीं, इन कार्यक्रमों के बाद जल स्रोतों पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसका आकलन भी नहीं हो पाया।

जल संरक्षण को लेकर की जा रही नई पहल अपने उद्देश्य में सफल रहती है तो इससे जल संकट की समस्या का काफी हद तक समाधान होगा

अब सूखते जल स्रोतों और नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथारिटी, यानी सारा अनूठी पहल करने जा रही है। सारा का गठन ही जल संरक्षण की मुहिम को एकीकृत तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। सारा द्वारा की जा रही यह पहल है राज्य में पहली बार जल उत्सव के आयोजन की। पहली जून से आरंभ होने वाला यह जल उत्सव एक सप्ताह तक चलेगा। इसके बाद जल संरक्षण और वर्षा जल को सहेजने के लिए वर्षभर तेजी से कार्य होंगे। अभियान के रूप में संचालित होने वाले इन कार्यों का खाका तैयार कर लिया गया है।

कलह भरा चुनावी माहौल

हृदयनारायण दीक्षित

संप्रति आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन चुनाव प्रचार में आदर्श नहीं दिखाई पड़ते

तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच भिड़ंत के दौरान बीच-बचाव करते सुरक्षाकर्मी। प्रेट्र

लोकसभा चुनाव से हम भारत के लोग एक साथ दो लाभ उठाते हैं। पहला संसदीय क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधि मिलता है। जनप्रतिनिधि से मतदाताओं के प्रति निष्ठावान रहने की अपेक्षा रहती है। मताधिकार के प्रयोग से ही सरकार मिलती है और प्रधानमंत्री भी। इसलिए चुनाव प्रचार को आदर्श संवाद से भरा-पूरा होना चाहिए। सभी दलों के लिए अपनी विचारधारा रखने का यह अवसर बड़ा मूल्यवान है। विचार और मुद्दा आधारित बहसें चुनाव को लोकतांत्रिक अंतर्संगीत से भर देती हैं, लेकिन इस चुनाव में उत्सवी अंतर्संगीत की जगह कलह देखने को मिल रहा है। वैसे तो सभी चुनावों में आरोप-प्रत्यारोप के कारण वातावरण तनावपूर्ण होता रहा है, लेकिन मौजूदा चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप की प्रकृति खासी आक्रामक है। भड़काऊ है। चुनावों के दौरान अक्सर कायम रहने वाले सामाजिक कोलाहल की जगह इस बार कलह ने ले ली है। आरोपों की तपिश मई की गर्मी से भी ज्यादा झुलसाने वाली है। वैचारिक असहमति की तुलना में शत्रु भाव दिखाई पड़ रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र झूठे आरोप हैं। फर्जी वीडियो भी प्रसारित किए जा रहे हैं। निराधार आरोप और प्रत्यारोप चुनावी उत्सव को कलह में बदल रहे हैं। धनबल का प्रभाव खतरनाक है ही। छल छद्म का दुरुपयोग झूठ की सीमा को पार कर रहा है। अर्धसत्य का प्रयोग राष्ट्रव्यापी है।

तनाव और कलह से भरा वातावरण राष्ट्रीय चुनौती है। आम जनों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। डा. आंबेडकर ने संविधान सभा में जब स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा था, तब उन्होंने मताधिकार को जनतंत्र का मूल आधार बताया था। इसीलिए सभा के सभी सदस्यों के मन में चुनावों को पवित्र बनाने की इच्छा थी। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि, 'दोषपूर्ण निर्वाचनों से लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे अपने मताधिकार के सदुपयोग से शासन में सुधार लाने और सरकार बदलने जैसी स्थिति को महत्व नहीं देंगे।' सभा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक निर्वाचन आयोग संबंधी अनुच्छेद-324 का प्रस्ताव पारित कर दिया। भारत के निर्वाचन आयोग की प्रशंसा दुनिया के अन्य देशों में भी होती है। वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव संपन्न कराने में प्रतिष्ठित रहा है, लेकिन वर्तमान में कलह भरे वातावरण में वह भी असहाय दिखाई पड़ रहा है।

संप्रति आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन चुनाव प्रचार में आदर्श नहीं दिखाई पड़ते। आयोग को सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों की औपचारिक जांच होती है, लेकिन इसका सकारात्मक लाभ नहीं मिलता। शब्द और अपशब्द का निर्णय करना कठिन है। दलों और नेताओं के बीच आत्मीयता नहीं दिखाई पड़ती। पहले के चुनावों में अभिव्यक्ति की मर्यादा के साथ ही परस्पर प्रेमभाव भी दिखता था। अपने-अपने दलों के प्रचार को गति देना, प्रतिपक्षी की बात काटना सामान्य था, लेकिन परस्पर आत्मीय बने रहना प्रशंसनीय था। इस चुनाव में सारी मर्यादाएं भंग होती दिखती हैं। शायद इसी कारण भी मतदान के प्रति लोगों में निराशा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान की हरसंभव अपील की जा रही है, लेकिन आरंभिक दो चरणों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। आयोग अकेले इस स्थिति का सामना कैसे कर सकता है? कटुतापूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को परस्पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

आदर्श चुनाव आचार संहिता में व्यक्तिगत आक्षेपों पर पाबंदी है, लेकिन चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत आक्षेपों का ही बोलबाला है। भाषा भी कटुतापूर्ण है, जबकि भाषा संवाद का माध्यम है। सुंदर शब्द संवाद को मधुर बनाते हैं। दलों को शब्द और अपशब्द में अंतर करना चाहिए। पतंजलि ने 'महाभाष्य' में बताया है कि एक ही शब्द अपने प्रयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ देता है। ऋग्वेद के अनुसार भाषा बुद्धि से शुद्ध की जाती है। अथर्ववेद में शब्द माधुर्य की स्तुति है कि हमारी जिह्वा का अग्रभाग मधुर हो और हम रोषपूर्ण वाणी भी मधुरता के साथ बोलें। वैदिक कालीन सभा एवं समितियों में मधुर बोलने की प्रतिस्पर्धा थी। उस परंपरा से इतर इस चुनाव में कटुतापूर्ण आक्षेपों की प्रतिस्पर्धा है। वरिष्ठजन जो बोलते हैं, उसी अनुसार स्थानीय नेता कड़वा बोलते हैं। ऐसे वातावरण में निर्वाचित प्रतिनिधि संसद और विधानमंडलों में इसी कटुता का प्रयोग करते हैं। सदनों को आत्मीयता का मंच बनाने के लिए पहले हमें चुनावी बहसों को आत्मीय एवं प्रेम पूर्ण बनाना होगा। जो भारत हजारों वर्ष पहले वैदिक काल से ही प्रेम पूर्ण वाणी का उपासक रहा है, उसी भारत के लोकसभा के चुनाव में शब्द के विकल्प अपशब्द क्यों हो गए हैं? समाचार माध्यमों का एक वर्ग भी ऐसे संवाद को महत्व देता है। अपने विपक्षी से सम्मानपूर्ण बात करना लोकतंत्र की शान है।

भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में शब्दों का विपुल भंडार है। यह शब्द प्रयोगकर्ता के उद्देश्य और विवेक पर निर्भर है। फेसबुक, एक्स (ट्विटर) आदि ने विचार अभिव्यक्ति का प्रभावी मंच दिया है। इसमें विचार प्रकट करने के अवसर हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक का सदुपयोग कम दिखाई देता है। इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग सत्य, शिव और सौंदर्य के लिए क्यों नहीं हो सकता? चैनलों पर बहसों में प्रतिभागी चिल्लाते हैं। कभी-कभी मारपीट की भी नौबत तक आ जाती है। समझ नहीं आता कि किसी घटना के वर्णन में आक्रामक वाक्यों के ही प्रयोग क्यों होते हैं? यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने 'रिपब्लिक' में ज्ञानवान गुणी लोगों के शासन को सर्वोच्च बताया है। भारतीय परंपरा में भी शासक में सदाचार युक्त गुणों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है, किंतु वर्तमान चुनाव में सब तरफ शोर है। कलह है। आक्रामकता है। परस्पर कटुता है। धनबल बाहुबल का प्रभाव है। ऐसी स्थिति चिंताजनक है। चुनाव युद्ध नहीं हैं। लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि और सरकार चुनने का अवसर हैं। निर्भीक मतदान मतदाता का मौलिक अधिकार है। राजनीतिक दल और नेता मिलजुलकर इस वातावरण को बदल सकते हैं। तभी हम चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव बना पाएंगे।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

राहुल के अमेठी छोड़ने का मतलब

उमेश चतुर्वेदी

जब आइएनडीआइए का सर्वोच्च नेता ही मुकाबला नहीं कर सकता तो दूसरे दल मोदी को कितनी चुनौती दे पाएंगे?

राहुल गांधी को अधिकार है कि वह देश में जहां से चाहें, वहां से चुनाव लड़ें। वह केरल से चुनावी अखाड़े में उतरें या फिर रायबरेली से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन राहुल सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वह सबसे पुरानी पार्टी के एक प्रकार से सर्वेसर्वा हैं। कांग्रेस उनके ही इशारे पर चलती है। ऐसे में अगर राहुल अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट अमेठी छोड़ अपने दादा, दादी और मां की रायबरेली सीट पर राजनीतिक दांव आजमाते हैं तो सवाल उठेगा। 2004 में अमेठी से ही राहुल ने संसदीय राजनीति का ककहरा सीखना शुरू किया था। उसके पहले यानी 1999 के आम चुनाव में वहां से उनकी मां सोनिया गांधी ने संसदीय पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने अगली बार इसे छोड़ बगल की रायबरेली सीट को चुन लिया। रायबरेली से सोनिया के श्वसुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी लगातार चुने जाते रहे। अपवाद 1977 का चुनाव रहा, तब जनता पार्टी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। राहुल 2004 से 2019 तक संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2019 के आम चुनाव में स्मृति इरानी के हाथों मात खाने के बाद भी राहुल को वायनाड के बजाय अमेठी के प्रतिनिधि के तौर पर ही ज्यादा जाना जाता रहा।

हमने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, उसमें संसद या विधानसभा की सीटों की पहचान लंबे समय तक उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों और परिवारों की सियासी जागीर के रूप में होती रही है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें एक तरह से नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक जागीर रही हैं। इसी वजह से राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने को सामान्य राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा जा रहा। अमेठी सीट का गठन 1967 में हुआ था, लेकिन इस पर पहली बार नेहरू-गांधी परिवार का कब्जा 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी के जीतने के बाद हुआ। 1998 के आम चुनाव को छोड़ दें तो तब से लेकर 2019 तक यह सीट या तो कांग्रेस के प्रथम परिवार के पास रही या फिर परिवार के किसी वफादार के पास। 1998 का चुनाव अपवाद रहा, जब भाजपा के संजय सिंह को जीत मिली। हालांकि संजय सिंह की पहचान भी नेहरू-गांधी परिवार के ही नजदीकी की रही। संजय गांधी के निधन के बाद अमेठी से राजीव गांधी 1991 तक लगातार जीतते रहे। उनके निधन के बाद उनके नजदीकी कैप्टन सतीश शर्मा जीतते रहे। 1999 में जब सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति शुरू की तो उन्होंने भी इसी सीट को अपने लिए उपयुक्त पाया। हालांकि अगले चुनाव में इसे अपने बेटे के लिए खाली कर दिया। जाहिर है अमेठी एक लोकसभा सीट भर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। इस वजह से इस सीट से नेहरू-गांधी परिवार के किसी सदस्य का लड़ना पार्टी के उत्साह का सबब बनता है। उसी अमेठी सीट से अब नेहरू-गांधी परिवार अलग हो गया।

नामांकन दाखिल करने रायबरेली पहुंचे राहुल। प्रेट्र

राहुल के अमेठी छोड़ने का संदेश दूर तक महसूस किया जाएगा। उन्होंने न सिर्फ स्मृति इरानी, बल्कि भाजपा से कम से कम उत्तर प्रदेश में हार मान ली है। कांग्रेस के जिस नेतृत्व पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती देने का दारोमदार है, वह खुद ही उनके सहयोगी को वाकओवर दे रहा है। इससे नेतृत्व की मजबूती पर प्रश्न उठ रहे हैं। अब स्मृति इरानी राहुल के खिलाफ और आक्रामक होंगी। अगर अमेठी से लड़ने वाला नेहरू-गांधी परिवार का सदस्य पराजित भी हो जाता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी तो होते, लेकिन हताश नहीं होते, लेकिन अब इसकी आशंका है। केरल के मौजूदा राजनीतिक हालात कांग्रेस के लिहाज से बेहतर माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में वामपंथी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेसी गठबंधन को समर्थन मिल सकता है। राहुल अभी वहीं यानी वायनाड से सांसद हैं और वहां से चुनाव लड़ भी रहे हैं।

यदि राहुल वायनाड और रायबरेली, दोनों से ही जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट खाली करनी होगी। अगर राहुल रायबरेली छोड़ेंगे तो गारंटी नहीं कि उपचुनाव में कांग्रेस को जीत ही मिले। अगर उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी तो केरल में यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस का आलाकमान राज्य को लेकर गंभीर नहीं है। इससे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं पर भी चोट पहुंचने का खतरा हो सकता है। रायबरेली से राहुल की उम्मीदवारी ने कांग्रेस के प्रथम परिवार की अंदरूनी खींचतान को लेकर जारी चर्चाओं को भी हवा दी है। अगर यह चर्चा तेज हुई तो तब कांग्रेसी कार्यकर्ता और ज्यादा उदासीन होंगे। इससे उत्तर प्रदेश में पहले से ही पस्त पड़ी कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी। अमेठी से राहुल के अलग हो जाने के बाद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आइएनडीआइए की उम्मीदों पर भी पानी फिरने की आशंका बढ़ गई है। इसका यह संदेश जा रहा है कि जब आइएनडीआइए का सर्वोच्च नेता ही अपनी पारंपरिक सीट पर मुकाबला नहीं कर सकता तो दूसरे दल मोदी को कितनी चुनौती दे पाएंगे।

अमेठी और रायबरेली से नेहरू-गांधी परिवार के रिश्ते की अहमियत और राजनीतिक संकेतों को अखिलेश यादव शायद ठीक से समझ रहे थे। इसी वजह से वह कांग्रेस को लगातार सुझाव दे रहे थे कि वहां से राहुल या नेहरू-गांधी परिवार का ही कोई सदस्य उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे भाजपा के लिए राह आसान नजर आने लगी है। ऐसे में पार्टी राहुल और नेहरू-गांधी परिवार पर और ज्यादा हमलावर तो होगी ही, इसके जरिये उत्तर भारत में कांग्रेस को शिकस्त देने की कोशिश भी करेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शुचिता

शुचिता अर्थात पवित्रता वह दिव्य गुण है जिसे गीता में सबसे बड़ी दैवी संपत्ति कहा गया है। सत्य, अहिंसा, अभय, स्वाध्याय, स्थिरता, निग्रह आदि गुण तब तक प्राप्त नहीं होते, जब तक जीवन में शुचिता न हो। इसके बिना मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कोई तप सफल नहीं होता। महर्षि पतंजलि ने आष्टांगिक योग साधना के लिए भी शुचिता को आवश्यक तत्व माना है। धर्म के दस लक्षणों में भी इसको विशेष स्थान प्राप्त है। सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, परंतु यह भी सत्य है कि बिना शुचिता के न शरीर स्वस्थ रह सकता है और न मस्तिष्क। फलतः कर्म में पवित्रता भी नहीं आ सकती।

वास्तव में जीवन और समाज का वास्तविक सौंदर्य शुचिता से ही निखरता है। इसलिए शुचिता के बिना न कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है और न सामाजिक। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुचिता आवश्यक है। धन पुरुषार्थ सिद्धि का कारण है। अतः इस जगत में कोई कार्य और सेवा धन के बिना संभव नहीं, परंतु अधिकांश सामाजिक बुराइयों के मूल में धन होता है, जिसका कारण धन की अपवित्रता होती है। हमारे शास्त्रों ने सभी शुचिताओं में धन की शुचिता को प्रमुख माना है।

शुचिता एक साधना है, जिसका साधक हर व्यक्ति को होना चाहिए। गांधी जी ने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में शुचिता को सर्वोपरि मानकर कहा- यह केवल वाह्य नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए, क्योंकि चित्तवृत्तियों और मन का शोधन इसी से होता है। शुचिता में ही ईश्वर का वास है। अतः इसके बिना न ईश्वर की भक्ति हो सकती है, न समाज की सेवा। फिर आत्ममंगल और जनमंगल कैसे हो सकता है? इसीलिए उनके रामराज्य की कल्पना का आधार शुचिता थी। अतएव सामाजिक बुराइयों के निवारणार्थ जीवन के प्रत्येक आचरण में शुचिता होनी चाहिए।

डा. सत्य प्रकाश मिश्र

विवाह संस्कार की गरिमा जरूरी

देवेंद्रराज सुथार

विवाह संस्कार में दो विपरीत लिंग के लोग जीवन भर साथ निभाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इसकी रीतियों का निष्ठा से पालन हो

हाल में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक मूल्यवान संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को सलाह दी है कि वे शादी की रीतियों का पालन किए बिना पति-पत्नी का दर्जा हासिल करने की कोशिश न करें। बीजा जैसी कुछ व्यावहारिक सहूलियतों के लिए बिना फेरे लिए शादी का रजिस्ट्रेशन न कराएं।

विवाह एक पवित्र बंधन है, एक संस्कार है, जिसकी भारतीय समाज में अपनी एक अहमियत है। विवाह कोई गाने, डांस करने, शराब पीने, खाने-पीने और दहेज लेने का आयोजन नहीं है। यह ऐसा अहम आयोजन है, जिसमें दो विपरीत लिंग के लोग जीवन भर साथ निभाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इसकी रीतियों का निष्ठा से पालन हो। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित पारंपरिक रीति-रिवाजों और समारोहों का सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर विवाह पंजीकृत होने के बाद भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा-सात में हिंदू विवाह के समारोहों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसका विवाह की वैधता के लिए पालन किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून की नजर में विवाह वैध नहीं माना जाता है। एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है।

हर हिंदू विवाह में फेरे और सप्तपदी की रस्म इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद पति-पत्नी जीवन के सफर पर साथ मिलकर आगे बढ़ें और जीवन के हर क्षेत्र में मिलकर काम करें। वे दोनों एक-दूसरे को सम्मान दें, एक-दूसरे को सहयोग करें। जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहे। लिहाजा हिंदू समाज में विवाह के महत्व पर न्यायालय का जोर व्यापक निहितार्थ रखता है। यह सतही विचारों के बजाय आपसी सम्मान, समझ और प्रतिबद्धता के आधार पर रिश्तों को महत्व देने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तेजी से बदलती दुनिया में जहां सामाजिक मानदंड विकसित हो रहे हैं, विवाह जैसी संस्थाओं की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला हैं। अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विवाह की संस्था को संजोएं और उसका सम्मान करें, इसे एक पवित्र बंधन के रूप में पहचानें, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और हमारे समुदायों के ताने-बाने को मजबूत करता है। विवाह के इस महत्व को समझें और इस रिश्ते में प्रवेश करने से पहले गंभीरता से विचार करें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सरल हो मतदान प्रक्रिया

'क्यों उदासीन हैं मतदाता' शीर्षक से युक्त आलेख में संजय गुप्त ने वर्तमान लोकसभा चुनाव के दो चरणों में मतदाताओं की उदासीनता के चलते पिछले आम चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत कम होने के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करते हुए यह ठीक ही कहा है कि मतदान न करने वाले लोग बाद में शिकायत करने के अधिकारी नहीं रह जाते। मतदान हर भारतीय नागरिक के अधिकार के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस कर्तव्य का निर्वहन आवश्यक है। बावजूद इसके नकारात्मक धारणा से ग्रस्त कुछ उदासीन लोग मतदान के लोकतांत्रिक महत्व को नहीं समझते और अपने महत्वपूर्ण मताधिकार के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता का एक कारण निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की बाध्यता भी है, जिसके सरलीकरण की जरूरत है। डिजिटल युग में मतदान की कारगर और विश्वसनीय तकनीक भी विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए मतदान के लिए प्रत्येक बालिग भारतीय नागरिक का यूनिक मतदान पहचान पत्र का बनना जरूरी है। इस पहचान पत्र को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए आधार नंबर से जोड़ दिया जाए। चुनाव के समय आधार नंबर से लिंक मतदान पहचान पत्र धारक को मतदान केंद्र के अलावा अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर से मतदान करने का विकल्प भी दिया जाए। इस सुविधा से मतदान को बहुत ही सहज बनाया जा सकता है, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर से मतदान करने की तकनीक में मत की विश्वसनीयता का उपक्रम करना आवश्यक है, ताकि मतदाता के मत की गोपनीयता बनी रहे और उसके मत का कोई दुरुपयोग भी न कर सके।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

सरकारी स्कूलों की सुधरे दशा

इन दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की दशा में पिछले कुछ वर्षों के प्रयासों से भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। देश के गरीबों की हालत को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की दशा सुधारने की प्रथम आवश्यकता है। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन के भविष्य का रास्ता चुन सकता है, लेकिन विचारणीय यह है कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई आज के प्रतियोगिता के दौर में बिल्कुल शून्य के बराबर है। देश में 60 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या की औसत आय 72 हजार रुपये सालाना से भी कम है। जबकि शहर के निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम एवं यूनिफार्म का एक साल का खर्चा प्रति विद्यार्थी पचास हजार रुपये से अधिक होता है। ऐसा नहीं कि यह समस्या आज ही उत्पन्न हुई है। जब से शिक्षा में निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप हुआ है, असल समस्या तभी से उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के ट्यूशन पर रोक के साथ-साथ परीक्षाओं में नकल करने पर सख्ती से रोक लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार को कोई अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं, अपितु केवल सरकार को अपनी मनसा और तंत्र में बदलाव करने की आवश्यकता है। देश में एक पाठ्यक्रम और एक यूनिफार्म होना चाहिए, तब अच्छी, समान और सच्ची शिक्षा होगी। यह नियम लागू होना चाहिए। जिससे सभी को एकसमान शिक्षा मिलने के साथ-साथ पाठ्यक्रम सस्ता हो जाएगा। निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम के नाम पर हो रही लूट पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। यूनिफार्म एक होने से गरीब और अमीर के बीच की खाई भी कम होगी। सही मायने में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की दशा बदलनी है और गरीब के बच्चों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से बनाना है तो सभी जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर सांसद, सभी मंत्री, आइएएस अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें, बस सरकार को यह आदेश कर अमल में लाना है।

प्रेमपाल सिंह, पलवल

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****